घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 306- मंगलवार 08- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

मध्यप्रदेश में जहरीली शराब से पिता-बेटा समेत 22 मौतें

112 की हालत बिगड़ी,शराब ठेकेदार समेत 30 पर केस,10 गिरफ्तार

सागर,07 सितम्बर 2026। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। मरने वालों में पिता-पुत्र भी शामिल हैं। 112 लोग ऐसे हैं,जिनकी जहरीली शराब पीने से हालत बिगड़ी है। उन्हें सागर और भोपाल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मामले में शराब बेंचने वाले ठेकेदार समेत 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 10 को अरेस्ट कर लिया गया है। सोमवार सुबह महेश रावत (55),श्याम बाई अहिरवार (50) और कृष्ण कुमार लोधी ने दम तोड़ा। इससे पहले एयरलिफ्ट कर भोपाल लाए गए राम प्रसाद लोधी की रविवार देर रात को मौत हुई थी। उनके पिता गोविंद लोधी ने भी रविवार को दम तोड़ दिया था। रामप्रसाद का छोटा भाई भूरे लोधी सागर में भर्ती है। वहीं, दोपहर में गूगरा खुर्द निवासी भगवान सिंह (35), खटोरा निवासी गोपाल आदिवासी (40) और देश कुमार लोधी, निवासी मुड़ना पैरा की भी मौत हुई है। जहरीली शराब से मरने वाले महेश के भतीजे श्रवण कुमार रावत ने बताया कि चाचा ने कल शाम को शराब पी थी,जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। वहीं, श्याम बाई के बेटे विट्ठल अहिरवार ने कहा...हम मामा के घर गमी में गए थे। मां घर में अकेली थी। उन्होंने गांव में किसी से मंगवाकर शराब पी ली। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सुबह उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे,जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। एक शख्स ने पूछा था...जहरीली शराब तो नहीं है बंडा थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार,फरियादी अनूप सिंह लोधी ने बताया कि उसके गांव में करीब 8 लोग अवैध रूप से शराब बेचते हैं। 4 सितंबर को वह अपने भतीजे राजेंद्र लोधी के साथ जुझार लोधी की दुकान पर गया था। जुझार ने बताया कि बरेठी के लाइसेंसी शराब ठेकेदार यशवंत सिंह,मनीष लोधी और बंडा निवासी आशीष साहू ने आकाश राय,रहीम खान,सत्यम,आशाराम,अरविंद, रविंद्र, रोहित, अनिकेत गंधर्व और माखन के माध्यम से अपनी गाड़ी से नया सस्ता ब्रांड भेजा है।

दुकानदार जुझार ने कहा...20 रुपए सस्ती मिलेगी

शराब दुकानदार जुझार लोधी ने कहा...ब्रांड वही है और इसे मनीष व आशीष ने शराब के फार्मूले से बनाया है। उसने कहा कि यह बाजार से 20 रुपए सस्ती मिलेगी। राजेंद्र ने जुझार की दुकान से 70 रुपए में एक क्वार्टर देशी शराब खरीदी और पी। रात में घर लौटने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे बंडा अस्पताल ले जाया गया, जहां से सागर रेफर किया गया। इलाज के दौरान राजेंद्र की मौत हो गई। करतार सिंह लोधी और दिग्विजय सिंह लोधी की भी शराब पीने से मौत हुई।

112 लोगों की हालत बिगड़ी

जहरीली शराब पीने के बाद करीब 112 लोगों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी है। इनमें से कई लोगों को सागर और भोपाल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में शराब में मेथेनॉल की मिलावट पाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने शराब ठेकेदार समेत करीब 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली पीजी हादसा...7 की मौत

मालिक राजस्थान से हिरासत में लिया गया

बेसमेंट में तोड़फोड़ से गिरी थी 5 मंजिला बिल्डिंग

नई दिल्ली,07 सितम्बर 2026। दिल्ली हॉस्टल के हॉस्टल के मालिक हरिराम बंसल को पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू टीम ने सोमवार सुबह मलबे से एक और शव निकाला। उधर 12 लोगों को बचाया गया है। इनमें 5 की हालत गंभीर है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू डॉग और कैमरे के सहायता से लोगों की तलाश की जा रही है। हॉस्टल हादसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। हॉस्टल 5 मंजिला इमारत में था, जो करीब 40 साल पुरानी थी। दिल्ली नगर निगम के रिकॉर्ड में इस इमारत को खतरनाक घोषित नहीं किया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इमारत के बेसमेंट में पिछले 7 दिनों से तोड़फोड़ का काम चल रहा था। बेसमेंट पहले से कमजोर था और उसमें पानी भी भरा हुआ था। खुदाई के दौरान एक पिलर खिसक गया, जिससे पूरी इमारत ढह गई। हादसे के समय वहां काम कर रहे मजदूर भी मलबे में दब गए।

सांसद मनोज कुमार झा ने पीएम मोदी को लेटर लिखा : आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने घटना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। इसमें उन्होंने सत्य निकेतन हॉस्टल हादसे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के रहने की व्यवस्था से जुड़े संकट को लेकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहां बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई हॉस्टल हैं। इनके आसपास ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज हैं। इसी वजह से यहां दिनभर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि, सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

हॉस्टल हादसे के लिए नगर निगम जिम्मेदार, सरकार भी जवाबदेही से नहीं बच सकती : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हॉस्टल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा...हादसे के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के हॉस्टलों की हालत बेहद दयनीय और खराब है। सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। अदालत ने एमसीडी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एनएचआरसी और दिल्ली विश्वविद्यालय को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, पुलिस ने हॉस्टल के मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।

तीनों सेनाओं के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को केंद्र की मंजूरी

नई दिल्ली,07 सितम्बर 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) की बैठक में तीनों सेनाओं के लिए लगभग एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इससे भारतीय सेना के लिए केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेकी व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल,सेल्फ-प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स,एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर,ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद की जाएगी। मंजूर किये गए प्रस्तावों में से लगभग 98 फीसदी खरीद भारतीय इंडस्ट्री से की जाएगी।

रक्षा बलों के अलग-अलग अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) यानी सैद्धांतिक एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी मिलने से तीनों सेनाओं को नए हथियार मिलने से युद्धक क्षमता मजबूत होगी। सेना के लिए खरीदे जाने वाले केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेकी व्हीकल प्रभावित क्षेत्र का पता लगाने, पहचानने, मॉनिटर करने और मार्किंग करने में सक्षम होंगे। हाई मोबिलिटी व्हीकल मुश्किल इलाकों

में ऑपरेशनल क्षमता,लॉजिस्टिक सपोर्ट और मोबिलिटी को बढ़ाएंगे। इसी तरह सेल्फ-प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स मुश्किल इलाकों में तेज और रिस्पॉन्सिव माइनलेइंग के मामले में जरूरी ऑपरेशनल क्षमता हासिल करेंगे। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और वायु सेना के लिए खरीदे जाएंगे,जो सभी इलाकों और ऑपरेशनल हालात में मुश्किल मिशन पूरे करेंगे। ट्रॉल टैंक और ब्रिज सिस्टम का इस्तेमाल अलग-अलग इलाकों में ऑपरेशन के दौरान लड़ने वाली टीमों को कम्पोजिट क्रॉसिंग देने के लिए किया जाएगा। नौसेना के लिए अरुधरा रडार, डिजाइन और डेवलपमेंट किया जायेगा। उसके बाद मरीन गैस टरबाइन खरीदने के लिए एओएन दिया गया। अरुधरा रडार अलग-अलग नेवल एयर स्टेशन पर मौजूदा एयर रूट सर्विलांस रडार की जगह लेगा और वॉरशिप प्रोपल्शन सिस्टम मैकेनिकल माइन लेयर्स विदेशी वेंडर पर निर्भरता कम करेगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय वायु सेना के लिए फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पस जैमर खरीदने और डिफेंस फोर्स सिक्योर एक्सेस कार्ड सिस्टम लगाने को भी मंजूरी दी गई। ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पस जैमर दुश्मनों के रडार के खिलाफ असरदार जैमिंग करेगा और डिफेंस फोर्स सिक्योर एक्सेस कार्ड सिस्टम मौजूदा पेपर वाले आइडेंटिटी कार्ड/पास/परमिट को इंटर ऑपरेबल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन-बेस्ड स्मार्ट कार्ड सिस्टम से बदल देगा।

तमिलनाडु, बंगाल, पुडुचेरी और असम की 6 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान...6 अक्टूबर को वोटिंग

नई दिल्ली,07 सितम्बर 2026। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु,पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा सीटों तथा असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन छह सीटों पर मतदान छह अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना नौ अक्टूबर को की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। आयोग के अनुसार तमिलनाडु की मदुरांतकम (अनुसूचित जाति) और धारापुरम (अनुसूचित जाति) विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। पुदुचेरी की थट्टानचावडी विधानसभा सीट तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर भी मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इन सभी सीटों पर रिक्तियां संबंधित निर्वाचित सदस्यों के इस्तीफे के कारण हुई हैं। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना नौ सितंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 19 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। मतदान छह अक्टूबर और मतगणना नौ अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के लिए शुद्ध एवं अद्यतन मतदाता सूची महत्वपूर्ण आधार है। संबंधित विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन फरवरी 2026 में किया जा चुका है।

9 सितंबर को जारी होगा नोटिफिकेशन

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन 9 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर होगी। अगले दिन यानी 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 19 सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।

6 अक्टूबर को मतदान, 9 अक्टूबर को मतगणना

सभी छह सीटों पर एक ही चरण में 6 अक्टूबर 2026 को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को मतगणना होगी और चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक पूरी चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2026 तक समाप्त हो जाएगी।

तमिलनाडु की दोनों सीटों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 23 फरवरी, पुदुचेरी की सीट के लिए 14 फरवरी, पश्चिम बंगाल की दोनों सीटों के लिए 28 फरवरी और असम की नगांव लोकसभा सीट के लिए 10 फरवरी को हुआ था। हालांकि, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक मतदाता सूचियों को लगातार अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। आयोग ने कहा है कि उपचुनाव के सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों और मतदाता सत्यापन पर्ची मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान सुचारू रूप से कराने के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की गई हैं।

मतदाता पहचान के लिए मुख्य दस्तावेज निर्वाचन फोटो पहचान पत्र होगा। हालांकि, मतदान केंद्र पर आधार कार्ड,मनरेगा रोजगार कार्ड,बैंक या डाकघर की तस्वीर वाली पासबुक,श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, वाहन चलाने का लाइसेंस, स्थायी खाता संख्या कार्ड,राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड,भारतीय पासपोर्ट,तस्वीर वाला पेंशन दस्तावेज,केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक कंपनियों के कर्मचारियों को जारी तस्वीर वाला सेवा पहचान पत्र,सांसदों,विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र भी दिखाया जा सकेगा।

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाला पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद

चंडीगढ़,07 सितम्बर 2026। पंजाब सरकार के विरोध के बावजूद जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने सोमवार सुबह पंजाब लोक भवन में आयोजित समारोह में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 37वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस मिश्रा से पहले जस्टिस शील नागू पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जून 2026 में उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। पंजाब सरकार ने जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति का रविवार को विरोध किया था। राज्य सरकार ने आपात बैठक बुलाकर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। सरकार का कहना था कि नियुक्ति के समय पंजाब सरकार की राय नहीं ली गई और निर्धारित एसओपी का उल्लंघन हुआ है। सरकार ने इसी आधार पर शपथ ग्रहण रोकने की मांग की थी। पूर्व घोषणा के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया। खुफिया एजेंसियों ने समारोह के दौरान विरोध की आशंका को लेकर इनपुट दिया था।

क्षेत्रीय परिषद में अब हो रही जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग : शाह

नई दिल्ली,07 सितम्बर 2026। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गोवा की राजधानी पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद अब विवाद समाधान की जगह जनकल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का साधन बन गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई भी विवाद नहीं बचा है,यह एक बड़ी उपलब्धि है। शाह ने यह भी कहा कि आज की बैठक में शामिल सभी मुद्दे मॉनीटरिंग के थे। राज्यों के बीच नदियों के कई विवाद भी क्षेत्रीय परिषद में हल किए गए हैं, बच्चों के कुपोषण, कम वजन पर भी हम क्षेत्रीय परिषदों में काम कर रहे हैं। आधार के पेनेट्रेशन को भी मॉनीटर कर रहे हैं और आयुष्मान भारत कार्ड को सफल करने के लिए भी यहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नवीन न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन और नशे के खिलाफ भारत की जंग को सफल करने के काम में भी पश्चिमी क्षेत्र को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटराइज़ेशन में भी महाराष्ट्र में 98 प्रतिशत और गुजरात में 92 प्रतिशत की दर से अच्छा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने गोबरधन का जो मॉडल खड़ा किया है, उसे भी राज्य अपनाएं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरात के

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल्ल के. पटेल शामिल थे। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी परिषद की बैठक में भाग लिया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी साइबर अपराधों के खिलाफ रणनीति को लगातार 'प्रगति' में मॉनीटर कर रहे हैं। सभी राज्यों के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एफसीएफआरएस से जुड़ जाएं। म्यूल हंटर एआई से एकीकृत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को प्रेरित करने की ज़रूरत है। अमित शाह ने कहा कि ग्रीन ऊर्जा में भी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के चारों राज्य भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत सरकार ने डेटा सेंटर के लिए एक बहुत ल्यूक्रेटिव पॉलिसी बनाई है, इसका अधिकतम फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के कामों में आगे बढ़ रही हैं। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि उन्नत पर्यटन, उच्च प्रति व्यक्ति आय और खदानों के कारण आर्थिक विकास में अपनी भौगोलिक स्थिति से कहीं अधिक योगदान गोवा का है। शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र कई दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र देश का सबसे बड़ा आर्थिक, औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। अमित शाह ने कहा कि दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के तीनों राज्यों का भी 7.8 प्रतिशत की विकास दर को हासिल करने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र को देश के आर्थिक विकास के वेस्ट ईंजन के रूप में जाना जाता है। गोवा में 1 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आते हैं और उनमें 5 लाख विदेशी टूरिस्ट होते हैं। गोवा की जीएसडीपी में 16 प्रतिशत आय पर्यटन क्षेत्र से आती है।

महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा बर्दाश्त नहीं करूंगा,मेरी जीत के पीछे महिलाएं हीं : सीएम विजय

नई दिल्ली,07 सितम्बर 2026। तमिलनाडु के सीएम विजय ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजय का यह बयान नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन की एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर की गई डबल मीनिंग टिप्पणी के विवाद के बीच आया है। पुलिस ने 4 अगस्त को उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया था।

विजय ने कहा...कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी : विजय ने कहा कि विकास के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। पुलिस का काम सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि राज्य के विकास की नींव मजबूत करना भी है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग कानून का पालन करते हैं, उनके लिए पुलिस दोस्त है और जो कानून नहीं मानते, उनके लिए पुलिस दुश्मन है। राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों को पुलिस के काम में दखल नहीं देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने यह कथित डबल-मीनिंग टिप्पणी 3 अगस्त को तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी। इसी दौरान भीड़ में 'तृषा, तृषा' के नारे लगे। आरोप है कि इस पर उदयनिधि ने कहा, 'पानी कहीं और पहुंचे या न पहुंचे, वहां जरूर पहुंचना चाहिए।' बाद में सफाई दी कि उनका इशारा कावेरी के पानी की ओर था। इसके बाद 4 अगस्त को उदयनिधि से पुलिस ने 8 घंटे तक पूछताछ की,जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

संपादकीय

देश में खर्च किया गया हर रुपया बनता है आय

भारत में उपभोक्ताओं की कमी नहीं है,लेकिन असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि उनके द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये से अधिक से अधिक आय का निर्माण हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह अपील कि नागरिक घरेलू वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता दें,केवल देशभक्ति का नारा नहीं बल्कि विकास के अर्थशास्त्र से जुड़ा एक स्पष्ट तर्क है।

जब कोई भारतीय नागरिक विदेश में छुट्टी मनाता है या आयातित सामान खरीदता है, तो खर्च का बड़ा हिस्सा विदेशी उत्पादन के पास चला जाता है। अर्थशास्त्र में इसे लीकेज कहते हैं। इसके विपरीत,जब वही पैसा घरेलू पर्यटन,भारतीय होटलों,स्थानीय परिवहन या देसी शादियों पर खर्च होता है, तो वह देश की सीमा के भीतर ही घूमता है। इससे डामेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ता है,क्योंकि एक व्यक्ति का खर्च ही दूसरे व्यक्ति की आय बनता है।

यह मल्टीप्लायर प्रभाव तब सबसे मजबूत होता है जब पैसा पर्यटन और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में पहुंचता है। ये क्षेत्र कम पूंजी में अधिक लोगों को रोजगार और वेतन प्रदान करते हैं। इससे आय किसी एक बड़ी कंपनी में केंद्रित होने के बजाय छोटे सेवा प्रदाताओं तक व्यापक रूप से फैलती है। इसके अलावा, जब भारतीय कंपनियां अपने उत्पादों की निरंतर घरेलू मांग देखती हैं,तो वे विनिर्माण और नई क्षमता निर्माण में निवेश करने के लिए भी प्रेरित होती हैं।

हालांकि,इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी आयात नुकसानदेह हैं। तेल, औद्योगिक मशीनरी और इलेक्ट्रानिक्स घटकों का आयात देश की उत्पादकता और निर्यात क्षमता को बढ़ाता है। ऐसे आयात भविष्य के उत्पादन का आधार बनते हैं। इसके विपरीत, सोने का अत्यधिक आयात या विदेशी यात्रा जैसी चीजें देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाए बिना केवल विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करती हैं। इस तर्क की एक महत्वपूर्ण सीमा भी है।

केवल संरक्षणवाद के नाम पर उपभोक्ताओं को घटिया या महंगा सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविक लाभ तब मिलता है जब विशाल घरेलू बाजार भारतीय कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का पैमाना देता है और बाजार की प्रतिस्पर्धा उन्हें गुणवत्ता सुधारने पर मजबूर करती है। अंतिम लक्ष्य हर रुपये को भारत में रोककर रखना नहीं, बल्कि देश में रहने वाले रुपये से इतनी उत्पादकता और आय पैदा करना है जो बाहर जाने वाले रुपये की भरपाई कर सके। इससे देश की आर्थिक सेहत बेहतर होगी।

सत्य निकेतन हादसा : जिम्मेदार अधिकारियों पर हो ठोस कार्रवाई

दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार को पांच मंजिला छात्र-पीजी भवन का भरभराकर गिर जाना केवल एक दर्दनाक हादसा नहीं है। यह उस व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है,जो भवन बनने देती है, उसमें अनधिकृत निर्माण होने देती है,

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

उसमें विद्यार्थियों को रहने देती है,उसकी कमजोरियों को वर्षों तक नजर अंदाज करती है और फिर उसके ढह जाने के बाद जागती है। इस हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की सूचना है और कई लोग घायल हुए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार भवन में बेसमेंट और कई ऊपरी मंजिलों में मरम्मत या निर्माण संबंधी काम चल रहा था। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच और भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि हादसे के बाद किसके खिलाफ एफआईआर होगी?असली सवाल यह है कि हादसे से पहले जिम्मेदार अधिकारी कहां थे? यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन था,यदि भवन का स्वीकृत नक्शा नहीं था,यदि अतिरिक्त मंजिलें बनाई गई थीं, यदि बेसमेंट में निर्माण चल रहा था,यदि भवन छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और यदि वह संरचनात्मक रूप से जोखिमपूर्ण था,तो इन सबका पता प्रशासन को तब क्यों नहीं चला जब वहां

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

निर्माण हो रहा था?

सत्य निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के आसपास विद्यार्थियों का प्रमुख इलाका है। देश के विभिन्न राज्यों से हजारों युवा यहां अपने भविष्य के सपने लेकर आते हैं। वे छोटे-छोटे कमरों, पीजी और किराये के मकानों में रहकर पढ़ते हैं। उनके माता-पिता अपनी जीवनभर की कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर लगाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि राजधानी में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब शिक्षा की तलाश में निकला युवा एक ऐसी इमारत में पहुंचता है,जिसकी नींव ही नियमों और सुरक्षा के साथ समझौते पर टिकी हो,तो विकास की हमारी पूरी अवधारणा कटघरे में खड़ी हो जाती है और यह कोई पहली चेतावनी नहीं है। 2022 में भी सत्य निकेतन में निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत ढहने से दो मजदूरों की मौत हुई थी और चार लोग घायल हुए थे। उस समय भी निर्माण कार्य, सुरक्षा और भवन की निगरानी पर सवाल उठे थे। लगभग चार साल बाद उसी इलाके में फिर एक बड़ी इमारत ढह गई। इसका अर्थ है कि हमने घटना से सबक लेने के बजाय घटना को एक समाचार की तरह देखा और आगे बढ़ गए।

यहां भ्रष्टाचार की बात करते समय एक सावधानी भी जरूरी है। किसी अधिकारी या व्यवसायी को बिना जांच दोषी ठहराना उचित नहीं। लेकिन यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि नियमों के विरुद्ध निर्माण को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया,निरीक्षण में लापरवाही हुई या किसी प्रकार की मिलीभगत रही,तो जिम्मेदारी केवल भवन मालिक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिसने नियम तोड़े और जिसने नियम तोड़ने दिए-दोनों को जवाबदेह बनाना होगा। सत्य निकेतन की त्रासदी को जुलाई 2024 के पुराने राजेंद्र नगर हादसे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वहां राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों-तनीया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालविन की मृत्यु हुई थी। सबसे भयावह तथ्य यह था कि बेसमेंट का उपयोग लाइब्रेरी के रूप में हो रहा था, जबकि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार उसे पार्किंग और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात सामने आई-हादसे से लगभग एक महीने पहले एक विद्यार्थी ने एमसीडी में शिकायत की थी।

भारत में भवन निर्माण के लिए नियमों की कमी नहीं है। नक्शा स्वीकृति, भवन उपविधियां,अग्नि सुरक्षा,संरचनात्मक सुरक्षा,अधिभोग प्रमाण-पत्र,पार्किंग, बेसमेंट के उपयोग-हर क्षेत्र के लिए नियम हैं। लेकिन समस्या नियमों की संख्या नहीं,उनके पालन की ईमानदारी है। जब किसी भवन में एक मंजिल की अनुमति हो और चार-पांच मंजिलें खड़ी हो जाएं,जब बेसमेंट स्टोरेज के लिए स्वीकृत हो और वहां लाइब्रेरी या व्यावसायिक गतिविधि चलने लगे, जब सड़क की जलनिकासी बाधित हो और फिर भी निर्माण चलता रहे-तो सवाल केवल नागरिक की मनमानी का नहीं है। सवाल उस पूरी निगरानी व्यवस्था का है, जो आंखों के सामने होने वाले बदलाव को देखने के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं करती। भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने का नाम नहीं है। भ्रष्टाचार वह भी है जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्तव्य को जानबूझकर न निभाए। किसी अवैध निर्माण को देखकर आंखें बंद कर लेना भी व्यवस्था के प्रति अपराध है। किसी भवन को जोखिमपूर्ण जानते हुए कार्रवाई न करना भी भ्रष्ट प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा है।

सरकारी भवन भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? मई 2024 में दिल्ली के आईटीओ स्थित सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आग लगी थी। 46 वर्षीय ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की धुएं में दम घुटने से मृत्यु हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार भवन पुराना था और उसमें आधुनिक फायर-स्प्रिंकलर व्यवस्था भी नहीं थी। यह घटना एक और सवाल सामने रखती है-जब सरकारी भवनों में भी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है,तो निजी और अनधिकृत भवनों की निगरानी की स्थिति क्या होगी? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और देश के अन्य महानगरों में अनियोजित शहरी विस्तार लगातार बढ़ रहा है।

हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए ज्ञान की रोशनी

दुनियाभर में लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्वभर में 'अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस' मनाया जाता है।

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़, नई दिल्ली

दुनिया से अशिक्षा को समाप्त करने के संकल्प के साथ इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। पहली बार यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) द्वारा 17 नवम्बर 1965 को 8 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी,जिसके बाद प्रथम बार 8 सितंबर 1966 से शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा विश्वभर के लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष इसी दिन यह दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। वास्तव में यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का ही प्रमुख घटक है।

निरक्षरता को खत्म करने के लिए ईरान के तेहरान में शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान वर्ष 1965 में 8 से 19 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए पहली बार बैठक की गई थी और यूनेस्को ने नवम्बर 1965 में अपने 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया। उसके बाद से सदस्य देशों द्वारा प्रतिवर्ष 8 सितंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस' मनाया जा रहा है। साक्षरता दिवस के अवसर पर निरक्षरता समाप्त करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देने तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के पक्ष में वातावरण तैयार किया जाता है। यह दिवस लगातार शिक्षा को प्राप्त करने की

ओर लोगों को बढ़ावा देने के लिए तथा परिवार,समाज और देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए मनाया जाता है।

दुनियाभर में आज भी अनेक लोग निरक्षर हैं और यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत,सामुदायिक तथा सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विश्व में सभी लोगों को शिक्षित करना ही है। साक्षरता दिवस के माध्यम से यही प्रयास किए जाते हैं कि इसके जरिये तमाम बच्चों, व्यस्कों, महिलाओं तथा वृद्धों को भी साक्षर बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में फिलहाल करीब चार अरब लोग साक्षर हैं लेकिन विड़म्बना यह है कि आज भी विश्वभर में करीब एक अरब लोग ऐसे हैं,जो पढ़ना-लिखना नहीं जानते। तमाम प्रयासों के बावजूद दुनियाभर में 77 करोड़ से भी अधिक युवा भी साक्षरता की कमी से प्रभावित हैं अर्थात प्रत्येक पांच में से एक युवा अब तक साक्षर नहीं है, जिनमें से दो तिहाई महिलाएं हैं। आंकड़े बताते हैं कि 6-7 करोड़ बच्चे आज भी ऐसे हैं, जो कभी विद्यालयों तक नहीं पहुंचते जबकि बहुत से बच्चों में नियमितता का अभाव है या फिर वे किसी न किसी कारणवश विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। कोरोना काल में यह समस्या और ज्यादा गहरी हुई। करीब 58 फीसदी के साथ सबसे कम व्यस्क साक्षरता दर के मामले में दक्षिण और पश्चिम एशिया सर्वाधिक पिछड़े हैं।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के लिए प्रतिवर्ष एक विशेष थीम चुनी जाती है और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है 'लोगों, धरती और समृद्धि के लिए साक्षरता'। वर्ष 2025 और 2024 में साक्षरता दिवस क्रमशः 'डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना' और 'बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना- आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता' थीम के साथ मनाया गया था। इस विशेष दिवस के लिए 2006 से लेकर अब तक निर्धारित थीम पर नजर डालें तो 2006 में सामाजिक प्रगति प्राप्ति पर ध्यान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय 'साक्षरता सतत विकास' रखा गया था। वर्ष 2007 और 2008 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की विषय-वस्तु 'साक्षरता और स्वास्थ्य' थी,जिसके जरिये टीबी, कॉलेरा,एचआईवी,मलेरिया जैसी फैलने वाली बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए महामारी के ऊपर ध्यान केन्द्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2009 में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देने के लिए इसका विषय 'साक्षरता और सशक्तिकरण' रखा गया था जबकि 2010 की थीम 'साक्षरता विकास को बनाए रखना' थी। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के लिए थीम 'साक्षरता और महामारी' (एचआईवी,क्षय रोग,मलेरिया आदि संक्रमणीय बीमारियों) पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए थी। 2012 में लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए थीम थी 'साक्षरता और सशक्तिकरण'। 2013 में शांति के लिए साक्षरता के महत्व पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 'साक्षरता और शांति',2014 में '21वीं शताब्दी के लिए साक्षरता', 2015 में 'साक्षरता और सतत विकास', 2016 में 'अतीत पढ़ना,भविष्य लिखना', 2017 में 'डिजिटल दुनिया में साक्षरता', 2018 में 'साक्षरता और कौशल विकास' अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम थी। 2019 में 'साक्षरता और बहुभाषावाद', वर्ष 2020 में 'कोविड-19 संकट और उससे संबंधित शिक्षा और शिक्षण',2021 में 'मानव-केन्द्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरताः डिजिटल विभाजन को कम करना' (लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन-सेंट्रड रिकवरीः नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड), 2022 में 'ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस' (साक्षरता सीखने के स्थान को बदलना) तथा 2023 में 'संक्रमण काल में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना : टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण' (प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशनः बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसायटीज) अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम थी।

बहरहाल,भारत हो या दुनिया के अन्य देश, गरीबी मिटाना, बाल मृत्यु दर कम करना,जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करना,लैंगिक समानता प्राप्त करना आदि समस्याओं के समूल विनाश के लिए सभी देशों का पूर्ण साक्षर होना बेहद जरूरी है। दरअसल साक्षरता ही सामाजिक विकास का आधार स्तंभ बन सकती है। साक्षरता में ही वह क्षमता है, जो परिवार और देश की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है। आंकड़े देखें तो दुनिया में 100 से भी अधिक देश अभी भी ऐसे हैं, जो पूर्ण साक्षरता हासिल करने के लक्ष्य से अभी दूर हैं और चिंता की बात है कि भारत भी इनमें शामिल है। हालांकि आजादी के बाद देश में साक्षरता दर काफी तेजी से बढ़ी है लेकिन अभी इस दिशा में बहुत किया जाना बाकी है।

भारतीय ज्ञान परंपरा से विकसित भारत 2047 तक : शिक्षा महाकुंभ का वैश्विक ज्ञान-संकल्प

भारत की पहचान केवल उसकी प्राचीन सभ्यता,संस्कृति और परंपराओं से नहीं,बल्कि उस विराट ज्ञान-संपदा से भी है,जिसने हजारों वर्षों से मानव जीवन को दिशा दी है। गणित,खगोल विज्ञान,चिकित्सा,दर्शन,

डॉ. गरिमा भाटी
नई दिल्ली

योग,कृषि,वास्तु,धातु विज्ञान,भाषा,साहित्य,कला और जीवन-मूल्यों से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा आज एक बार फिर वैश्विक विमर्श के केंद्र में आ रही है। इसी व्यापक दृष्टि को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा महाकुंभ अभियान के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर बहु-ट्रैक सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी श्रृंखला में अर्नी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश में विकसित भारत 2047 के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ : परंपराओं को जोड़ते हुए भविष्य का रूपांतरण विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा की समकालीन प्रासंगिकता पर केंद्रित

होगा। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणालियों के विविध आयामों को आधुनिक शिक्षा,विज्ञान,प्रौद्योगिकी,शासन,संस्कृति और सतत विकास के संदर्भ में समझना तथा विकसित भारत के निर्माण में इसकी संभावनाओं को सामने लाना है।

अर्नी विश्वविद्यालय और समग्र शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन देश-विदेश के शिक्षाविदों,शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं,शिक्षकों और युवा शोधार्थियों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन में भारतीय ज्ञान प्रणाली के विविध आयामों पर अंतर्विषयक संवाद को प्रोत्साहित किया जाएगा। विज्ञान एवं अभि यांत्रिकी से लेकर कला एवं मानविकी,संविधान एवं शासन तथा व्यवसाय एवं प्रबंधन तक अनेक क्षेत्रों को सम्मेलन के विमर्श में शामिल किया गया है।

विशेष रूप से भारतीय वैज्ञानिक विरासत एवं नवाचार,स्वदेशी ज्ञान का संरक्षण एवं प्रमाणीकरण, आयुर्वेद, योग एवं ध्यान,भारतीय दर्शन,ज्योतिष,पारंपरिक ज्ञान प्रणा लियाँ,सतत विकास,कृषि एवं कृषि प्रणालियाँ,सांस्कृतिक विरासत, भारतीय संविधान,सामाजिक न्याय, नेतृत्व,उद्यमिता तथा भारतीय व्यवसाय परंपराओं जैसे विषयों पर विचार-विमर्श प्रस्तावित है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को केवल अतीत की धरोहर के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए उपयोगी ज्ञान-स्रोत के रूप में देखने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल, विकसित भारत 2047 का सपना केवल आर्थिक विकास या तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं हो सकता। विकास तभी पूर्ण माना जाएगा,जब उसमें ज्ञान,मूल्य,संस्कृति,पर्यावरण,सामाजिक उत्तर दायित्व और मानवीय संवेदन शीलता का संतुलन हो। भारतीय ज्ञान परंपरा इसी समग्र दृष्टि की आधारभूमि तैयार करती है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ भारतीय चिंतन की जीवन-दृष्टि का समन्वय आने वाले समय में शिक्षा को अधिक मानवीय, रचनात्मक और उत्तरदायी बना सकता है। इसी व्यापक उद्देश्य के साथ शिक्षा महाकुंभ अभियान शिक्षा को केवल डिग्री और रोजगार तक सीमित रखने के बजाय उसे राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। बहु-ट्रैक सम्मेलनों के माध्यम से अलग-अलग विषयों, संस्थानों और विचारों को एक मंच पर लाकर ऐसा ज्ञान-संवाद तैयार किया जा रहा है,जिसमें शोध केवल शोधपत्र तक सीमित न रहे,बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य से जुड़े प्रश्नों के समाधान का माध्यम बने।

इस अभियान का सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण पड़ाव 9 से 11 अक्टूबर तक देवभूमि हिमाचल की पावन धरती पर आयोजित होने वाला शिक्षा महाकुंभ 6.0 होगा। निस्संदेह यह आयोजन वैश्विक शिक्षा जगत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर सिद्ध होगा। यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आने वाले'वैश्विक ज्ञान युग'की उद्घोषणा है। देश-विदेश के शिक्षाविदों,शोधकर्ताओं,शिक्षकों,विद्यार्थियों और नीति-निर्माताओं के लिए यह ऐसा मंच होगा,जहाँ विचार केवल व्यक्त नहीं होंगे,बल्कि भविष्य का निर्माण करेंगे।

शिक्षा महाकुंभ की मूल भावना यही है कि भारत अपनी ज्ञान परंपरा को संग्रहालयों में सुरक्षित रखने वाली विरासत के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य को दिशा देने वाली जीवंत शक्ति के रूप में पहचाने। भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का संवाद ही उस भारत की आधारशिला बन सकता है,जो आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ विश्व को भी दिशा देने में सक्षम हो।

आज आवश्यकता है कि हम अपनी परंपरा को आँख मूंदकर स्वीकार करने या पूरी तरह नकारने के बजाय उसे वैज्ञानिक दृष्टि,शोध और समकालीन संदर्भों में समझें। यही दृष्टिकोण शिक्षा को जड़ों से जोड़ते हुए भविष्य की ओर ले जाएगा।

शिक्षा महाकुंभ 6.0 इसी संकल्प का महाअभियान है परंपरा से प्रेरणा, ज्ञान से नवाचार और शिक्षा से विकसित भारत की ओर।

कानून सुरक्षा का कवच हो...भय का हथियार नहीं

भारत का संविधान समानता,गरिमा और न्याय का वादा करता है। इसी संवैधानिक भावना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम बनाया गया। यह कानून उन सामाजिक परिस्थितियों की देन है,जिनमें सदियों से भेदभाव और हिंसा झेलने वाले समुदायों को सामान्य कानून से अतिरिक्त संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई।

इसलिए इस कानून की आवश्यकता और उसकी मूल भावना पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं होगा। सवाल उस व्यवस्था को लेकर है,जो किसी भी कानून को लागू करते समय न्याय और निष्पक्षता के बीच संतुलन कैसे कायम रखे।

आज देश में यह बहस लगातार सामने आ रही है कि क्या किसी कानून के दुरुपयोग की संभावना को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है? यह प्रश्न केवल किसी एक जाति या वर्ग का नहीं है। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध झूठा या दुर्भावनापूर्ण मुकदमा दर्ज होता है,तो उसका नुकसान उसकी जातीय पहचान देखकर कम या ज्यादा नहीं होता। उसकी प्रतिष्ठा, रोजगार,परिवार और मानसिक शांति सभी प्रभावित होते हैं।

लेकिन दूसरी ओर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि फर्जी मामलों की आशंका को वास्तविक अत्याचार के मामलों में शिकायत दर्ज कराने की राह में बाधा न बनने दिया जाए। यही वह महीन रेखा है, जहां कानून और संवेदनशीलता दोनों की परीक्षा होती है। किसी भी आपराधिक कानून का उद्देश्य दोषी को दंड और निर्दोष को सुरक्षा देना होना चाहिए। इसलिए शिकायत मिलते ही पीड़ित की सुरक्षा, साक्ष्य का संरक्षण और कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। लेकिन जांच की प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आरोप और अपराध को एक ही चीज न मान लिया जाए।

एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि नहीं है। दोष सिद्ध करने का अधिकार न्यायालय को है। इसलिए जांच के दौरान आरोपी के संवैधानिक अधिकारों और पीड़ित के कानूनी अधिकारों–दोनों की रक्षा जरूरी है।

विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां विवाद की पृष्ठभूमि संपत्ति,आपसी रंजिश, पारिवारिक विवाद,स्थानीय राजनीति या दूसरे गैर-सामाजिक कारणों से जुड़ी हो, पुलिस जांच को तथ्यपरक और निष्पक्ष बनाना बेहद जरूरी है। जांच अधिकारी को केवल शिकायत के शब्दों पर नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों,घटनाक्रम,गवाहों और परिस्थितियों को भी देखना चाहिए।

यहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। गंभीर और तात्कालिक हिंसक अपराधों में किसी भी प्रकार की देरी पीड़ित के हित में नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे मामलों में जहां तत्काल गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, कानून और न्यायालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के भीतर आरोपी के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

अग्रिम जमानत का प्रश्न भी इसी संतुलन से जुड़ा है। कानून ने एससी/ एसटी एक्ट के मामलों में विशेष प्रावधान इसलिए रखे हैं ताकि प्रभावशाली आरोपी कानून की प्रक्रिया को प्रभावित न कर सकें और पीड़ितों को न्याय से वंचित न किया जा सके। मगर न्यायपालिका ने समय-समय पर यह सिद्धांत भी स्पष्ट किया है कि यदि शिकायत प्रथम दृष्ट्या कानून के प्रावधानों को आकर्षित ही नहीं करती या मामला स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है,तो न्यायिक समीक्षा का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हो सकता।

इसलिए समाधान कानून को कमजोर करना नहीं,बल्कि जांच को मजबूत करना है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में जातिगत अत्याचार का शिकार हुआ है,तो उसे पुलिस थाने,प्रशासन और न्यायालय के चक्कर लगाते हुए वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे सुरक्षा, सम्मान और शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। वहीं यदि कोई व्यक्ति निजी दुश्मनी या संपत्ति विवाद के कारण झूठे मुकदमे में फंसाया गया है,तो उसके साथ भी कानून को आंखें बंद करके नहीं चलना चाहिए।

फर्जी शिकायत साबित होने पर जवाबदेही का प्रश्न भी गंभीरता से उठना चाहिए। हालांकि केवल किसी मामले में आरोपी के बरी हो जाने को स्वतः 'फर्जी मुकदमा' नहीं माना जा सकता। दुर्भावना और झूठे आरोप को प्रमाणित करने के लिए भी उचित न्यायिक प्रक्रिया आवश्यक है। अन्यथा शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का डर वास्तविक पीड़ितों को शिकायत करने से रोक सकता है।

यही कारण है कि इस विषय पर भावनाओं से अधिक प्रक्रियात्मक सुधार की जरूरत है।

पुलिस अधिकारियों के लिए वैज्ञानिक जांच,डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण, शिकायतों की तथ्यपरक जांच और वरिष्ठ स्तर पर निगरानी की व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए। जहां कानून अनुमति देता है,वहां न्यायिक निगरानी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, जानबूझकर झूठे आरोप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई का प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू होना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बहस को जातीय संघर्ष का रूप नहीं दिया जाना चाहिए...

एससी/एसटी समुदाय की सुरक्षा बनाम ओबीसी या सामान्य वर्ग की सुरक्षा–इसे दो विरोधी खेमों की लड़ाई बनाना स्वयं समाज के लिए नुकसानदेह होगा। न्याय का कोई जातीय संस्करण नहीं हो सकता। अत्याचार करने वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो,उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और निर्दोष व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो,उसे कानून की सुरक्षा मिलनी चाहिए।

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती इसी में है कि वह कमजोर को संरक्षण देती है और निर्दोष को न्याय।

इसलिए आज जरूरत ऐसे कानूनी ढांचे की है जिसमें पीड़ित की आवाज दबे नहीं और निर्दोष की आवाज कुचली भी न जाए। कानून इतना मजबूत हो कि अत्याचारी उससे डरें और इतना निष्पक्ष हो कि निर्दोष नागरिक उस पर भरोसा कर सकें।

राजनीतिक प्रभाव,सामाजिक दबाव या व्यक्तिगत रंजिश के लिए किसी भी कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कानून किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, अपराध के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।

अंततः प्रश्न यह नहीं है कि सुरक्षा कवच किस वर्ग को मिले। असली प्रश्न यह है कि कानून का कवच हर उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचे जिसे न्याय की वास्तविक जरूरत है।

एससी/एसटी एक्ट की मूल भावना–सामाजिक न्याय और अत्याचार से सुरक्षा–अक्षुण्ण रहनी चाहिए। साथ ही ऐसी प्रक्रियात्मक व्यवस्था विकसित करनी होगी,जिसमें दुर्भावनापूर्ण मुकदमेबाजी की गुंजाइश कम से कम हो और निर्दोष नागरिक वर्षों तक मुकदमे का बोझ ढोने के लिए मजबूर न हों।

कानून का डर अपराधी को होना चाहिए, निर्दोष को नहीं।

यही किसी भी सभ्य लोकतंत्र में न्याय की सबसे बड़ी कसौटी है।यदि इसे और धारदार राजनीतिक-सामाजिक संपादकीय बनाना हो, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसलों और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के संदर्भ जोड़कर इसे राष्ट्रीय अखबार के संपादकीय पृष्ठ के स्तर का बनाया जा सकता है।

सुदामा राजवाड़े
राजपुर,बलरामपुर,छ.ग.

हिंदी कवितायें

गुलजार

उदय किशोर साह
जयपुर जिला बांका बिहार

कहाँ छुप गई हो मेरी प्यारी रूखसार
मेरा दिल तेरे बिन है कब से।बेकरार
सामने आ जा सनम कर लूँ दीदार
मेरे जीवन की हमसफर मेरे दिलदार
पहाड़ों की चोटी कर रहा है पुकार
तैर कर आ जा नदिया के इस पार
साहिल पे बैठा करता हूँ इन्तजार
कर दे मेरी तन्हा रातें आज गुलजार
जन्मों जन्मों के हम हैं दो। हमराही
प्यार में अच्छी नहीं होती है बेवफाई
तुँ नहीं हो सकती हो कभी भी पराई
दिल के कागज पे है तुम कसमें खाई
तुम मेरी चन्दा तुम जीवन की चाँदनी
मेरे दिल की
वीणा की हो तुम वादिणी
छेड़ दो साज की
तुम अंगुली से। तार
संगीत की घुल जाये फिजां में बहार
एक दुजे में खो जायें
जैसे नदी की संगम
जमाना मूक देखेगा
हमारी प्यार हरदम
दो दिल की मिलन
का हो प्यार का बंधन
हमारे प्यार को
करेगा जग फ़िर वन्दन

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

हाइवे पर हाट बाजार का कब्जा...थम गई वाहनों की रफ्तार

हाट बाजार ने रोक देती है हाइवे की रफ्तार,अजिरमा में रविवार जाम का खतरा

अजिरमा में सड़क तक सजी दुकानें और बेतरतीब पार्किंग बनी जाम की वजह...राहगीर परेशान-हादसे के खतरे के बीच स्थायी समाधान की मांग...

हाइवे पर दुकानें,सड़क पर पार्किंग... अजिरमा में थम गई रफ्तार

अजिरमा हाट बाजार बना यातायात का 'चक्रव्यूह',हाइवे पर वाहनों की कतार

दुकानों ने घेरा हाइवे,पार्किंग ने बढ़ाई मुश्किल-अजिरमा में यातायात बेहाल

अजिरमा हाट में बाजार से ज्यादा दिखता है जाम, हाइवे पर हर कदम खतरा

हाइवे पर सजता बाजार,फंसता यातायात-अजिरमा में व्यवस्था पर सवाल

-संवाददाता-
अंबिकापुर,07 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

जिला मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजिरमा का साप्ताहिक हाट बाजार रविवार के दिन स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है,सप्ताह में एक दिन लगने वाला यह बाजार आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए खरीदारी और छोटे व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है,लेकिन बाजार के दिन सड़क किनारे बढ़ती भीड़,हाईवे की पटरियों तक फैली दुकानें और बेतरतीब तरीके से खड़े किए जाने वाले वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनती है। बाजार के दिन सड़क के दोनों ओर सब्जी,फल,कपड़े,घरेलू सामान,किराना सहित अलग-अलग तरह की दुकानें लगती हैं, कई स्थानों पर दुकानों का फैलाव सड़क के मुहाने तक पहुंच जाता है,दूसरी ओर बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोग अपने दोपहिया और चारपहिया वाहनों को सड़क किनारे या दुकानों के सामने खड़ा कर देते हैं,इससे हाईवे पर वाहनों के लिए उपलब्ध जगह कम हो जाती है,सामान्य दिनों की तुलना में बाजार के दिन यातायात दबाव बढ़ने के कारण कई बार वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती है और जाम जैसी स्थिति निर्मित होने की शिकायत सामने आती है।

सड़क पर अचानक पहुंचते हैं ग्राहक,बढ़ता है खतरा

हाईवे पर सबसे बड़ी चिंता सड़क सुरक्षा को लेकर है, बाजार में खरीदारी करने आए लोग दुकान से दूसरी दुकान तक जाने के दौरान कई बार सड़क के काफी करीब पहुंच जाते हैं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी बाजार में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं,दूसरी तरफ हाईवे से लगातार छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही होती रहती है,ऐसी स्थिति में वाहन चालक को अचानक सामने आए व्यक्ति या वाहन से बचने के लिए ब्रेक लगाना पड़ सकता है, यदि पीछे से कोई दूसरा वाहन तेज गति से आ रहा हो तो स्थिति जोखिमपूर्ण हो सकती है,विशेष रूप से भारी वाहनों की मौजूदगी में सड़क किनारे पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहनों की आवाजाही अतिरिक्त सावधानी की मांग करती है,बाजार क्षेत्र में यातायात को लेकर कोई छोटी सी चूक भी दुर्घटना का कारण बन सकती है,यही वजह है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या को गंभीर रूप लेने से पहले बाजार और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जरूरत है।

बेतरतीब पार्किंग भी बनी बड़ी समस्या

अजिरमा हाट बाजार में केवल दुकानों का सड़क तक फैलना ही परेशानी का कारण नहीं है,बल्कि ग्राहकों और दुकानदारों द्वारा वाहनों को निर्धारित स्थान के अभाव में जहां जगह मिली,वहां खड़ा कर देना भी यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है,चारपहिया वाहन सड़क किनारे खड़े होने के बाद सड़क की चौड़ाई और कम हो जाती है,दोपहिया वाहन भी यदि व्यवस्थित तरीके से खड़े न हों तो पैदल चलने वालों और अन्य वाहनों के लिए परेशानी पैदा करते हैं,बाजार समाप्त होने तक वाहनों की आवाजाही और पैदल लोगों की भीड़ बनी रहती है, यदि बाजार के लिए पहले से पार्किंग क्षेत्र तय कर दिया जाए और वहां वाहनों को खड़ा कराने की व्यवस्था की जाए तो सड़क पर होने वाली भीड़ को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

हाईवे की चौड़ाई सिमटने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक-अजिरमा का साप्ताहिक हाट स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है,आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां सामान खरीदने और बेचने पहुंचते हैं, छोटे व्यापारी और ग्रामीण अपनी उपज सहित अन्य सामान लेकर बाजार में आते हैं,ऐसे में बाजार क्षेत्र में लोगों और वाहनों की आवाजाही स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है,समस्या तब गंभीर हो जाती है जब सड़क की पटरियों और आसपास उपलब्ध स्थान के बजाय दुकानें हाईवे के नजदीक तक पहुंच जाती हैं,ग्राहकों के वाहन भी सड़क के किनारे खड़े होने लगते हैं, एक ओर दुकानें और दूसरी ओर पार्क किए गए वाहन होने से सड़क का उपयोग करने वाले वाहनों के लिए जगह सीमित हो जाती है, छोटे वाहन किसी तरह निकल जाते हैं,लेकिन बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों के गुजरने के दौरान स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। कई जगह वाहन चालकों को गति कम करनी पड़ती है, सामने से आने वाले वाहनों के साथ जगह बनाने में भी परेशानी होती है, परिणामस्वरूप बाजार क्षेत्र में यातायात की गति प्रभावित होती है।

एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को लेकर चिंता-बाजार क्षेत्र में यातायात प्रभावित होने का सबसे गंभीर पहलू आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा है,यदि बाजार के समय किसी कारण से सड़क पर लंबा जाम लग जाता है तो एम्बुलेंस,दमकल या अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हो सकता है,आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाले मरीज के लिए समय बेहद महत्वपूर्ण होता है,ऐसे में बाजार क्षेत्र में किसी भी स्थिति में ऐसा स्थान उपलब्ध रहना चाहिए,जहां से आपातकालीन वाहन बिना बाधा गुजर सकें,स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार को हटाना या छोटे व्यापारियों की आजीविका प्रभावित करना समस्या का एकमात्र समाधान नहीं है,जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है,जिसमें व्यापारियों को कारोबार की जगह मिले और हाईवे का आवागमन भी बाधित न हो।

सप्ताह में एक दिन लगता है बाजार, पहले से बनाई जा सकती है व्यवस्था-स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों का कहना है कि अजिरमा में हाट बाजार सप्ताह में एक निर्धारित दिन लगता है, ऐसे में प्रशासन और संबंधित विभाग के पास बाजार वाले दिन के लिए पहले से यातायात प्रबंधन की योजना बनाने का अवसर रहता है,बाजार शुरू होने से पहले दुकानों के स्थान निर्धारित किए जा सकते हैं,सड़क से निश्चित दूरी तक किसी भी दुकान को नहीं लगाने की व्यवस्था की जा सकती है, इसी तरह बाजार में आने वाले वाहनों के लिए अलग पार्किंग स्थल तय किया जा सकता है, यदि बाजार के दिन यातायात पुलिस अथवा संबंधित अमले की आवश्यकतानुसार तैनाती की जाए तो सड़क पर दुकानों के फैलाव और बेतरतीब पार्किंग को नियंत्रित किया जा सकता है, इससे वाहन चालकों को भी परेशानी कम होगी और बाजार आने वाले लोगों को भी सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

दुकानदारों की भी मजबूरी,कार्रवाई के बजाय विकल्प जरूरी-सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारी और ग्रामीण दुकानदार इस बाजार से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, सप्ताह में एक दिन लगने वाला हाट उनके लिए आय का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है, ऐसे में केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर समस्या का समाधान करना स्थायी रास्ता नहीं माना जा सकता,जरूरत इस बात की है कि प्रशासन बाजार की वास्तविक स्थिति का आकलन करे और दुकानदारों के लिए व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराए,यदि हाईवे से कुछ दूरी पर पर्याप्त जगह चिन्हित कर हाट बाजार विकसित किया जाता है तो दुकानदारों को भी स्थायी सुविधा मिल सकती है,इसके साथ ही बाजार क्षेत्र में पैदल चलने वालों के लिए स्थान, वाहनों के लिए पार्किंग और दुकानों के लिए निर्धारित क्षेत्र तय किया जा सकता है, इससे व्यापार भी जारी रहेगा और हाईवे पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी।

वैकल्पिक हाट बाजार स्थल की उठ रही मांग-स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों की मांग है कि अजिरमा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के लिए सुरक्षित और पर्याप्त स्थान चिन्हित किया जाए। बाजार को हाईवे से पर्याप्त दूरी पर व्यवस्थित किया जाए ताकि मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित न हो, लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन,यातायात पुलिस और स्थानीय निकाय मिलकर बाजार का सर्वे कर लें तो समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है,इसके लिए बाजार क्षेत्र की उपलब्ध जमीन,दुकानदारों की संख्या, ग्राहकों की संख्या और पार्किंग की आवश्यकता का आकलन किया जाना जरूरी है।

नो-पार्किंग और यातायात नियंत्रण से मिल सकती है राहत

बाजार स्थल के आसपास नो-पार्किंग क्षेत्र निर्धारित करना भी तत्काल राहत देने वाला कदम हो सकता है,हाईवे के दोनों ओर निर्धारित दूरी तक वाहनों की पार्किंग रोकने के साथ ग्राहकों के लिए अलग पार्किंग स्थल उपलब्ध कराया जाए तो सड़क पर वाहनों का दबाव कम किया जा सकता है,इसी तरह बाजार के दिन दुकानों को सड़क की सीमा से पीछे रखने, पैदल आवागमन के लिए पर्याप्त जगह छोड़ने और भारी वाहनों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है।

प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती— व्यापार भी चले,यातायात भी-अजिरमा हाट बाजार की समस्या को केवल जाम अथवा अतिक्रमण के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा, एक तरफ छोटे व्यापारियों और ग्रामीणों की आजीविका जुड़ी है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले हजारों यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए,जिसमें किसी एक पक्ष को नुकसान न हो, बाजार के लिए अलग और व्यवस्थित स्थल उपलब्ध कराया जाए, दुकानदारों को निश्चित स्थान मिले,ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा हो और हाईवे को पूरी तरह यातायात के लिए खुला रखा जाए।

समय रहते नहीं चेते तो बढ़ सकती है परेशानी-अजिरमा हाट बाजार में वर्तमान व्यवस्था यदि इसी तरह चलती रही तो आने वाले समय में यातायात का दबाव और बढ़ सकता है,सड़क किनारे दुकानें,बढ़ती भीड़ और बेतरतीब पार्किंग का संयोजन सड़क सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है, स्थानीय लोगों की मांग है कि किसी दुर्घटना या बड़ी जाम की स्थिति बनने का इंतजार करने के बजाय प्रशासन अभी से ठोस कदम उठाए,बाजार के लिए सुरक्षित स्थान,पार्किंग व्यवस्था,नो-पार्किंग जोन और बाजार वाले दिन यातायात नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से लागू की जा सकती हैं, लोगों का कहना है कि मुद्दा बाजार बंद कराने का नहीं,बल्कि बाजार को व्यवस्थित कराने का है, यदि प्रशासन दुकानदारों और स्थानीय लोगों से चर्चा कर व्यावहारिक समाधान तैयार करता है तो व्यापारियों की आजीविका भी सुरक्षित रह सकती है और हाईवे पर वाहनों की रफ्तार भी बनी रह सकती है।

स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें...

- हाईवे से पर्याप्त दूरी पर साप्ताहिक हाट बाजार के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित किया जाए।
- बाजार में आने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अलग पार्किंग स्थल बनाया जाए।
- बाजार वाले दिन हाईवे के दोनों ओर नो-पार्किंग व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू की जाए।
- आवश्यकता के अनुसार यातायात पुलिस या संबंधित अमले की तैनाती की जाए।
- दुकानों को हाईवे और सड़क के मुहाने से पर्याप्त दूरी पर व्यवस्थित किया जाए।
- छोटे व्यापारियों के लिए वैकल्पिक वेंडिंग जोन अथवा निर्धारित बाजार क्षेत्र विकसित किया जाए।
- बाजार क्षेत्र में एम्बुलेंस,दमकल और अन्य आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता हर समय खुला रखा जाए।
- बाजार व्यवस्था को लेकर प्रशासन, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय से स्थायी समाधान तैयार किया जाए।

चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया सरगुजा का नाम

100 व 200 मीटर में स्वर्ण,रिले में रजत,बने सर्वश्रेष्ठ एथलीट,SGFI में करेंगे NVS का प्रतिनिधित्व

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

जवाहर नवोदय विद्यालय अंबिकापुर के छात्र चंद्रशेखर प्रधान ने गुजरात के डांग जिले में आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर सरगुजा को गौरवान्वित किया है। चंद्रशेखर ने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक,जबकि 4×100 मीटर रिले में रजत पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चंद्रशेखर को देशभर के करीब 700 जवाहर नवोदय विद्यालयों के खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 'सर्वश्रेष्ठ एथलीट' के सम्मान से नवाजा गया। इसके साथ ही उनका चयन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए हुआ है, जहां वे नवोदय विद्यालय समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे। चंद्रशेखर की उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य राजू दुबे ने खुशी जताते हुए कहा कि उसकी मेहनत,अनुशासन और लगन ने विद्यालय के साथ पूरे सरगुजा का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास, सही मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। विद्यालय के खेल प्रशिक्षक सालोमी इक्का एवं अजय पांडेय ने बताया कि चंद्रशेखर की सफलता उसके नियमित अभ्यास, आत्मविश्वास,अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। तीन पदकों के साथ सर्वश्रेष्ठ एथलीट का सम्मान मिलना उसके कठिन परिश्रम को दर्शाता है। SGFI के लिए उसका चयन विद्यालय और जिले के लिए गौरव की बात है।

चंद्रशेखर की सफलता में विद्यालय के शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिक्षकों ने उसे निरंतर प्रोत्साहित करने के साथ खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रखने में सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया। चंद्रशेखर की उपलब्धि से जवाहर नवोदय विद्यालय अंबिकापुर में खुशी का माहौल है। विद्यालय परिवार ने उसे बधाई देते हुए SGFI प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

उनकी सफलता ने यह साबित किया है कि सरगुजा की प्रतिभाएं राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने का पूरा सामर्थ्य रखती हैं।

महिलाओं और छात्राओं को साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक....

साइबर जागृति अभियान के तहत स्मार्टफोन प्राइवेसी, सोशल मीडिया सुरक्षा और शिकायत प्रक्रिया की दी जानकारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

डिजिटल युग में ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'साइबर जागृति अभियान' के तहत सरगुजा पुलिस ने महिलाओं एवं छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रमों में महिला कॉलेजों की छात्राओं, महिला सामुदायिक समूहों एवं विभिन्न महिला संगठनों से जुड़ी महिलाओं को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन की प्राइवेसी सेटिंग्स,सुरक्षित ब्राउजिंग तथा सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखने के व्यावहारिक तरीके बताए गए। पुलिस टीम ने समझाया कि मोबाइल एप को आवश्यकता से अधिक परमिशन,जैसे कैमरा, गैलरी और लोकेशन की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और प्रोफाइल लॉक की दी जानकारी : फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्रिय करने तथा प्रोफाइल लॉक जैसे सुरक्षा फीचर्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। साथ ही लॉटरी, इनाम, मुफ्त रिचार्ज और फर्जी नौकरी के नाम पर भेजे जाने वाले संदिग्ध लिंक से सावधान रहने तथा फिशिंग वेबसाइटों की पहचान करने के तरीके भी बताए गए। पुलिस ने महिलाओं को निजी तस्वीरें, लाइव लोकेशन, आधार नंबर और बैंक संबंधी संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा करने के जोखिमों से भी अवगत कराया। साइबर स्टॉकिंग,ऑनलाइन बुलिंग और अवांछित संदेशों की स्थिति में ब्लॉक एवं रिपोर्ट फीचर का उपयोग करने की जानकारी दी गई।

सवालों के माध्यम से समझी साइबर सुरक्षा : कार्यक्रम को संवादात्मक रखा गया। छात्राओं ने साइबर अपराध से जुड़े सवाल,अनुभव और अपनी शंकाएं पुलिस टीम के सामने रखीं, जिनका अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सरल भाषा में समाधान किया। पुलिस ने कहा कि साइबर अपराध या ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार होने पर घबराने के बजाय तत्काल पुलिस से संपर्क करना चाहिए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in और हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी भी दी गई। पुलिस ने महिलाओं एवं छात्राओं से अपील की कि किसी भी साइबर ठगी या ऑनलाइन अपराध की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराएं,ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

CMYK

शिक्षक दिवस पर भाजपा सोनहत मंडल का अनूठा अभियान

घर-घर पहुंचकर शिक्षकों और समाज को दिशा देने वाले वरिष्ठजनों का सम्मान

-राजन पाण्डेय-

सोनहत,07 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सोनहत मंडल ने इस बार पारंपरिक आयोजनों से अलग पहल करते हुए 'गुरुजनों के द्वार सम्मान' अभियान चलाया,भाजपा मंडल के कार्यकर्ता स्वयं शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों,वरिष्ठ नागरिकों तथा विभिन्न क्षेत्रों में समाज को दिशा और प्रेरणा देने वाले सम्मानित व्यक्तित्वों के घर पहुंचे और शॉल-श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। अभियान का उद्देश्य केवल शिक्षक दिवस मनाना नहीं, बल्कि उन व्यक्तित्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना रहा,जिन्होंने अपने ज्ञान, संस्कार, अनुभव और सामाजिक योगदान से पीढ़ियों को दिशा देने का कार्य किया है, कार्यकर्ताओं ने सम्मानित गुरुजनों एवं वरिष्ठजनों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनके अनुभवों से प्रेरणा लेने और समाज व राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प लिया,यह अभियान भाजपा मंडल अध्यक्ष राजाराम राजवाड़े,जिला पंचायत सदस्य शिवकुमारी सोनपाकर,जनपद पंचायत सोनहत अध्यक्ष आशा देवी सोनपाकर एवं भाजपा जिला मंत्री ईश्वर राजवाड़े के नेतृत्व में आयोजित किया गया। मंडल के पदाधिकारियों,कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर सम्मान कार्यक्रमों को पूरा किया।

बड़ी संख्या में गुरुजनों और वरिष्ठजनों का सम्मान-अभियान के दौरान देव नारायण पोया,नान साय राजवाड़े, जगमोहन राजवाड़े,कुंदन लाल राजवाड़े, बीरेंद्र तिवारी,रवि पाण्डेय,राम साय राजवाड़े, माया राम राजवाड़े,देव सागर राजवाड़े,राम सागर,मनबसिया,अर्जुन राजवाड़े,ईश्वर राजवाड़े, सुमित राजवाड़े, बनस लाल सीलर, विनोद साहू,राम विशाल साहू, आलम साय राजवाड़े, रवि शंकर साहू, राम केश्वर साहू, शुभ शरण सिंह, उदय सिंह, राज कुमार सोनपाकर, हरि सिंह, देवदत्त सिंह, लक्ष्मण साहू, आनंद पांडेय, रेशमा पांडेय, विजय गुप्ता, प्रवीण पाण्डेय, राम जूठन साहू, बलदाऊ भारतीय, राज कुमार राजवाड़े, अयोध्या दुबे, सुरेश राजवाड़े, वीर साय, हृदय लाल राजवाड़े, संगीता राजवाड़े, बदन सिंह, रघुवर शर्मा, सतेंद्र शर्मा, रोशनी यादव, मुल्करण दुबे, फूनेनं सिंह, कृष्णा चेरवा, शोभनाथ, प्रभु नारायण, राम साय यादव, वीरेंद्र यादव, धर्म साय राजवाड़े, भवन राजवाड़े, शिव प्रसाद राजवाड़े, श्याम कुमार राजवाड़े, हरगोविंद राजवाड़े, मनी लाल चेरवा, रामगोपाल साहू, सूरज कुमार, नान साय पण्डो, महेश कुमार, बृज कुमार, श्याम लाल यादव, अवधेश दुबे, प्रदीप पाण्डेय, शिव शंकर कवलवंशी, सुनीता सिंह, लीलाधर पैकरा, कमल साय, कांति पैकरा, राजेश सिंह, चंदा सिरे, धर्म साय, अघन साय, राम दास, अंजू देवी, सत्यनारण, फूलमति एक्का, राम केश मार्को, लोकेश टोप्पो, राम बदन सिंह, कृष्णा कुमारी, रसना कुमारी, राजेश सिंह, राम नरेश पैकरा, प्रदीप तिर्की, राम कृपाल राजवाड़े, कृष्णा देवी, बसंत राम यादव, अंजू राजवाड़े, शैलेश कुमार सैनी, परीक्षित चंद्र तिर्की, उमेश कुमार पाण्डेय, मान साय राजवाड़े, सुदीप चौबे, अर्जित तिर्की, वेद प्रकाश यादव, सोनेलाल मिंस, उषा कुजूर, आनंद कुमार इक्का, सुकांत समरल, पूर्णिमा सिंह, बाल साय सोनपाकर, मीना भगत, ओम प्रकाश तिर्की, संजय सरकार, ओम प्रकाश कुर्रे, अजय सिंह, सुरेश कुमार साहू, कांति राजवाड़े, प्रतिमा सिंह, लक्ष्मण राम भगत, राजेश दास महंत, वंदना कंवर, महेश कुमार पटेल, अजय सिंह, सुनीता कंवर, रामायण कंवर, सूर्यकांत सेठ, सोहे लाल राजवाड़े, निलेश कुमार कुशवाहा, बृजभान सिंह, राजकुमार पाल, दुलेश्वर प्रसाद, अनिमा कुजूर एवं पार्वती पैकरा सहित बड़ी संख्या में शिक्षकों एवं समाज के प्रेरणादायी वरिष्ठजनों का सम्मान किया गया।

सम्मान के साथ लिया आशीर्वाद- भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाज में बदलाव केवल योजनाओं और संसाधनों से नहीं, बल्कि संस्कार और मार्गदर्शन से भी आता है, शिक्षकों और वरिष्ठजनों ने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए समाज की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, ऐसे व्यक्तित्वों का सम्मान नई पीढ़ी में भी अपने गुरुजनों और वरिष्ठों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करता है, कार्यकर्ताओं ने सम्मानित गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हुए कहा कि उनके ज्ञान और जीवन अनुभव को समाज की नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है, उनका मार्गदर्शन सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को बेहतर दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पूरे मंडल में चला सम्मान अभियान- सोनहत मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों और समाज के सम्मानित नागरिकों के घर पहुंचकर उनका अभिनंदन किया, इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर समाज में योगदान देने वाले लोगों से मुलाकात की और उनके अनुभव सुने, अभियान में मंडल के पदाधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही, कार्यकर्ताओं के अनुसार घर-घर पहुंचकर सम्मान करने की इस पहल से शिक्षक दिवस का संदेश सीधे समाज के बीच पहुंचा।

औपचारिकता से आगे बढ़कर सम्मान की पहल-शिक्षक दिवस पर सामान्य तौर पर विद्यालयों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। सोनहत मंडल की पहल की खास बात यह रही कि कार्यकर्ता स्वयं सम्मानित व्यक्तित्वों के घर पहुंचे, इससे सम्मान केवल मंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत संपर्क और संवाद के रूप में सामने आया,भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुरुजनों और वरिष्ठजनों का सम्मान किसी एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, समाज को दिशा देने वाले इन व्यक्तित्वों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना निरंतर बनी रहनी चाहिए,अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षकों का ज्ञान,वरिष्ठजनों का अनुभव और युवाओं की ऊर्जा मिलकर समाज को मजबूत आधार दे सकती है,इसी भावना के साथ भाजपा सोनहत मंडल के कार्यकर्ता भविष्य में भी समाज के प्रेरणास्रोत व्यक्तित्वों के सम्मान और उनके अनुभवों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कार्य करते रहेंगे।

विद्यालय से आगे समाज के मार्गदर्शक हैं शिक्षक

अभियान के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षक की भूमिका केवल विद्यालय में विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने तक सीमित नहीं होती, शिक्षक समाज में ज्ञान,संस्कार,अनुशासन, नैतिकता और कर्तव्यबोध की भावना विकसित करने वाला मार्गदर्शक होता है,इसी तरह समाज के वरिष्ठजन अपने जीवन के लंबे अनुभवों के माध्यम से नई पीढ़ी को सही दिशा देने का काम करते हैं,इसी विचार के साथ सोनहत मंडल ने शिक्षक दिवस को केवल किसी एक स्थान पर औपचारिक कार्यक्रम आयोजित कर मनाने के बजाय गुरुजनों और वरिष्ठजनों के घर तक पहुंचकर उनका सम्मान करने का निर्णय लिया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिन लोगों ने अपना जीवन समाज और नई पीढ़ी के निर्माण में लगाया है, उनके द्वार तक पहुंचकर सम्मान करना स्वयं कार्यकर्ताओं के लिए भी गौरव का विषय है।

एचआईवी-एड्स के प्रति जागरूकता और भेदभाव खत्म करने दिलाई शपथ

होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजन

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,07 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज, अंबिकापुर में प्राचार्य डॉ. सिस्टर शांता जोसेफ के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एचआईवी/एड्स एवं एचआईवी/एड्स अधिनियम-2017 विषय पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एचआईवी/एड्स से प्रभावित लोगों के प्रति भेदभाव समाप्त करने, उनके सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा करने की शपथ दिलाई गई। छात्राओं को सेल्फ असेसमेंट स्कैनर के माध्यम से Self Risk Assessment की जानकारी दी गई और इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया।

रेड रिबन क्लब की नोडल अधिकारी दिव्या सिंह ने एचआईवी/एड्स से संबंधित वैज्ञानिक एवं सही जानकारी साझा करते हुए जागरूकता तथा भेदभाव-मुक्त व्यवहार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं को एचआईवी/एड्स से जुड़ी भ्रांतियों से बचने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उप प्राचार्य डॉ. सिस्टर मंजू टोप्पो, महाविद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

रांग नंबर से युवती के मोबाइल पर आया फोन फिर प्रेम,शादी का झांसा देकर बलात्कार

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,07 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर अंबिकापुर थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 69 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, बलरामपुर जिले के 24 वर्षीय युवती ने शिकायत में बताया है कि वह वर्ष 2020 से अंबिकापुर के नमनाकला में किराए के मकान में अपनी बहन के साथ रहती थी। मार्च 2020 में उसके मोबाइल पर एक रांग नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने अपना नाम सूर्यकांत बड़ा निवासी भकुरमा, थाना उदयपुर बताया। इसके बाद दोनों के बीच लगातार मोबाइल पर बातचीत होने लगी। शिकायत के अनुसार, सूर्यकांत ने युवती से प्रेम और शादी करने की बात कही। इसके बाद वह अंबिकापुर स्थित उसके किराए के कमरे में आता था और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। युवती ने आरोप लगाया कि 25 अगस्त 2026 की रात करीब 11 बजे भी सूर्यकांत ने जोड़ा पीपल क्षेत्र स्थित किराए के कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती के अनुसार, 27 अगस्त को उसने सूर्यकांत से शादी करने के लिए कहा तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और उसे जो करना है करने की बात कहते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। इसके बाद युवती ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी और 5 सितंबर को राजपुर थाने में लिखित शिकायत की।

छात्राओं के पैदल मार्च ने खोली एकलव्य विद्यालय की अव्यवस्था

तीन माह से बिजली गुल,विषय शिक्षक भी नहीं,कलेक्टर ने जांच टीम गठित कर दो दिन में मांगी रिपोर्ट

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,07 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बतौली के शिवपुर स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को उस समय प्रशासन में हड़कंप मच गया,जब 100 से अधिक छात्राएं समस्याओं का समाधान कराने अंबिकापुर के लिए पैदल निकल पड़ीं। छात्राओं ने विद्यालय में तीन महीने से बिजली नहीं होने के साथ फिजिक्स-केमेस्ट्री के शिक्षक नहीं होने, भोजन की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायत की है। करीब छह किलोमीटर पैदल चलने के बाद प्रशासन ने बस की व्यवस्था कर छात्राओं को अंबिकापुर पहुंचाया। छात्राएं करीब छह किलोमीटर ही चली थीं कि इसकी जानकारी जिला प्रशासन को मिली।

प्रशासन ने तत्काल बस की व्यवस्था कर छात्राओं को अंबिकापुर पहुंचाया। पहले उन्हें करीब एक घंटे तक पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में रखा गया। इसके बाद छात्राओं को कलेक्टोरेट ले जाया गया, जहां उन्होंने

कलेक्टर अजीत बसंत के समक्ष विद्यालय की समस्याएं रखीं।

सहायक आयुक्त को दी थी जानकारी : छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में फिजिक्स और केमेस्ट्री के शिक्षक नहीं हैं। बिजली की समस्या के साथ भोजन की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इन समस्याओं की जानकारी प्राचार्य और आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ललित शुक्ला को भी दी गई थी,लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके बाद छात्राओं ने सीधे कलेक्टर से शिकायत करने का निर्णय लिया।

सहायक आयुक्त से छात्राओं ने नहीं की बात : छात्राओं के पैदल निकलने की जानकारी मिलने पर सहायक आयुक्त ललित शुक्ला भी रास्ते में उनसे मिलने पहुंचे। हालांकि छात्राओं ने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालय के शिक्षक भी छात्राओं के साथ रहे।

जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित : कलेक्टर अजीत बसंत ने छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं की जांच के लिए टीम गठित की है। टीम में संयुक्त कलेक्टर शारदा अग्रवाल, एसडीएम सीतापुर फागेश सिन्हा और आदिवासी विकास विभाग की सहायक संचालक किरण राजपूत शामिल हैं। टीम को विद्यालय पहुंचकर जांच करने और दो दिन के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एक छात्रा की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

कलेक्टोरेट पहुंचने के दौरान एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। वहीं, अन्य छात्राओं को दो बसों से वापस विद्यालय भेज दिया गया। कलेक्टर ने आश्रम-छात्रावासों के नोडल अधिकारियों को भी एक सप्ताह के भीतर सभी छात्रावासों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

रावण दहन आयोजन को भव्य बनाने नागरिक सेवा समिति ने की बैठक

आपसी सामंजस्य से आयोजन कराने पर जोर,सरगुजा सेवा समिति के अध्यक्ष को पत्र भेजकर रखी बात

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,07 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

आगामी दशहरा पर्व पर होने वाले सार्वजनिक रावण दहन आयोजन को लेकर नागरिक सेवा समिति की आवश्यक बैठक समिति के वरिष्ठ सदस्य अजय अग्रवाल के निवास पर आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने रावण दहन कार्यक्रम की तैयारियों एवं आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में सदस्यों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से नगर के इस प्रमुख आयोजन को नागरिक सेवा समिति, सरगुजा सेवा समिति एवं जिला प्रशासन की बराबर भागीदारी और आपसी सहयोग से संपन्न कराया जाता रहा है। सदस्यों के अनुसार, पिछले

कुछ वर्षों से नागरिक सेवा समिति के सदस्य स्वयं को आयोजन में अपेक्षित भूमिका नहीं मिलने के कारण उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सदस्यों ने कहा कि दशहरा नगर का प्रमुख सार्वजनिक आयोजन है और इसे लेकर किसी प्रकार की गलतफहमी या मनभेद नहीं होना चाहिए। सभी संस्थाओं के बीच आपसी सामंजस्य एवं सहयोग के साथ आयोजन को पहले की तरह भव्य और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से नागरिक सेवा समिति की ओर से सरगुजा सेवा समिति के अध्यक्ष को पत्र भी प्रेषित किया गया है, जिसमें आयोजन को मिल-जुलकर पूरे उत्साह के साथ सफल बनाने की बात कही गई है। बैठक में सदस्यों ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए दशहरा पर्व के रावण दहन कार्यक्रम को शहरवासियों के लिए भव्य एवं अविस्मरणीय बनाएंगे। बैठक में अजय अग्रवाल, त्रिलोक कपूर कुशवाहा, जेपी श्रीवास्तव, शफी अहमद, द्वितेंद्र मिश्रा, राजीव अग्रवाल, नुरुल अमीन सिद्दीकी, नीरज पांडे, राधे कृष्ण गोयल, जीवन यादव, चंद्र प्रकाश सिंह, अभिषेक शुक्ला, संदीप जायसवाल, ऋषभ गर्ग, सुनील गोयल, विवेक अग्रवाल, दुर्गेश गुप्ता, आशीष जायसवाल, अंकित जायसवाल, दिनेश शर्मा, विकास शर्मा एवं दीपक कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

खाना नहीं बनने पर भड़का पति,फावड़े से सिर पर किया वार,पत्नी की मौत,घटना के कुछ घंटे बाद आरोपी पति गिरफ्तार...

-संवाददाता-

खड़गवां 07 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

थाना खड़गवां क्षेत्र के ग्राम गिद्धमुड़ी में खाना नहीं बनने की बात को लेकर पति द्वारा पत्नी के सिर पर फावड़े से हमला किए जाने का मामला सामने आया है, हमले में गंभीर रूप से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई, पुलिस ने मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी मिथनु पिता भारत सिंह गोड़, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम गिद्धमुड़ी थाना खड़गवां की रिपोर्ट पर प्रारंभ में थाना बैकुंठपुर में बिना नंबर मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया था, मृतिका के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पीएम रिपोर्ट एवं मर्ग डायरी थाना खड़गवां प्राप्त हुई,

इसके बाद थाना खड़गवां में मर्ग क्रमांक 70/26, धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक मर्ग जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट,नक्शा पंचायतनामा, सूचक एवं गवाहों के कथनों के परीक्षण और अवलोकन में घटना को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। जांच में बताया गया कि आरोपी रंजीत सिंह पिता स्व. रामलाल सिंह,उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम गिद्धमुड़ी ने 3 सितंबर 2026 की सुबह करीब 7 बजे अपनी पत्नी लक्ष्मनिया बाई से खाना मांगा था।

पंजाब मजदूरी करने गए किशोर की संदिग्ध मौत,ठेकेदारों पर गंभीर आरोप

बेहोशी की हालत में घर छोड़ गए ठेकेदार,कुछ घंटे बाद हुई मौत...आदिवासी समाज ने एफआईआर और उच्चस्तरीय जांच की मांग की...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,07 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम चेरा निवासी 17 वर्षीय आदिवासी किशोर युवराज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला गंभीर होता जा रहा है। परिजनों और सर्व आदिवासी समाज का आरोप है कि करीब तीन महीने पहले मजदूरी के लिए पंजाब के लुधियाना ले जाए गए किशोर को दो ठेकेदार 5 सितंबर को बेहोशी की हालत में एंबुलेंस से उसके घर छोड़कर चले गए। शाम को परिजन घर लौटे तो युवराज बेहोश मिला। कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग छत्तीसगढ़ ने सरगुजा संभाग के कमिश्नर और आईजी को ज्ञापन सौंपकर ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

समाज और परिजनों के अनुसार युवराज खैरवार जनजाति से था। आरोप है कि करीब तीन महीने पहले दो ठेकेदार उसे पाइपलाइन के काम के लिए लुधियाना ले गए थे।

परिजनों की सहमति के बिना किशोर को ले जाने और इस दौरान मजदूरी का भुगतान नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि 5 सितंबर को युवराज को एंबुलेंस से बेहोशी की हालत में उसके घर लाया गया। उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। आरोप है कि ठेकेदार उसे घर में छोड़कर चले गए। शाम को परिजन लौटे तो युवराज बेहोश मिला। शाम करीब 7 बजे उसकी मौत हो गई।

बीमारी की जानकारी नहीं देने पर उठे सवाल : परिजनों का आरोप है कि ठेकेदारों ने युवराज की तबीयत खराब होने, उपचार कराने या उसकी हालत के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। सर्व आदिवासी समाज ने सवाल उठाया है कि यदि काम के दौरान किशोर की तबीयत बिगड़ी थी तो उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया गया और तत्काल परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी गई। समाज ने मामले में बाल श्रम, अनुसूचित जनजाति से जुड़े कानूनी प्रावधानों और कथित मानव तस्करी के पहलुओं की भी जांच की मांग की है।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन

प्रदेश उपाध्यक्ष उदय कुमार पंडो के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में संबंधित ठेकेदारों और मामले में संलिप्त अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर,निष्पक्ष जांच तथा पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने की मांग की गई है। समाज ने चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर धरना-प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। समाज ने उच्चस्तरीय जांच कर किशोर की मौत की वास्तविक वजह सामने लाने की मांग की है।

CMYK

स्कूल में खुली अंतरिक्ष की दुनिया...कोरिया के नवाचार को राष्ट्रीय सम्मान

बच्चों की जिज्ञासा को मिली उड़ान,कोरिया के शैक्षणिक नवाचार को राष्ट्रीय पहचान

किताबों से निकलकर स्कूल की लैब तक पहुंचा अंतरिक्ष...कोरिया के नवाचार को राष्ट्रीय पहचान

किताब से आगे बढ़ी पढ़ाई,स्पेस लैब ने कोरिया को दिलाई राष्ट्रीय पहचान

स्पेस लैब से साइंस लर्निंग तक,कोरिया की नई शिक्षा पद्धति का राष्ट्रीय सम्मान

रॉकेट साइंस सेएआई तक,कोरिया के स्कूलों में बदली विज्ञान की पढ़ाई

जहां बच्चे पढ़ते थे अंतरिक्ष की कहानी, अब वहीं लैब में समझ रहे उसकी तकनीक

स्पेस लैब बनी बच्चों की जिज्ञासा की प्रयोगशाला,कोरिया को राष्ट्रीय पहचान

प्रयोग से सीखने की पहल रंग लाई,कोरिया के शैक्षणिक नवाचार को राष्ट्रीय सम्मान

स्पेस लैब,साइंस लर्निंग लैब और आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा ने बदली सीखने की तस्वीर,शैक्षणिक प्रशासन एवं नवाचार के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र गुप्ता राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित

-रवि सिंह-

कोरिया,07 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

अंतरिक्ष की दुनिया हमेशा से बच्चों के लिए कौतूहल और कल्पना का विषय रही है। चांद, तारे,ग्रह,रॉकेट और अंतरिक्ष मिशन के बारे में अब तक अधिकांश बच्चे किताबों,तस्वीरों और समाचार चैनलों के माध्यम से ही जानकारी हासिल करते रहे हैं,लेकिन कोरिया जिले में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों ने इस सोच को बदलने की कोशिश की है,यहां अंतरिक्ष विज्ञान को केवल किताब के अध्याय तक सीमित रखने के बजाय बच्चों की जिज्ञासा और प्रयोग आधारित सीखने से जोड़ने की पहल की गई है,स्पेस लैब और साइंस लर्निंग लैब जैसी पहल ने विद्यार्थियों को विज्ञान एवं तकनीक को करीब से समझने का अवसर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इन्हीं नवाचारों, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए कोरिया के जिला शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र गुप्ता को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है,3 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया, जिला शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र गुप्ता ने यह सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री डॉ. जे.एस. राजपूत के हाथों प्राप्त किया, कार्यक्रम में कार्यक्रम निदेशक श्रीमती विनीता सिरोही,वाइस चांसलर श्रीमती शशिकला वंजारी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए शैक्षणिक प्रशासन एवं नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है,इस सम्मान के साथ कोरिया जिले में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयोगों और नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

अंतरिक्ष अब केवल किताब का विषय नहीं...

स्कूली बच्चों के लिए स्पेस यानी अंतरिक्ष हमेशा से सबसे रोमांचक विषयों में शामिल रहा है, बच्चे रॉकेट की तस्वीर देखते हैं,अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं और टीवी पर अंतरिक्ष मिशन देखते हैं,लेकिन इन चीजों को प्रत्यक्ष रूप से समझने और उनके पीछे काम करने वाली तकनीक को जानने का अवसर सीमित होता है,कोरिया जिले में इसी दूरी को कम करने का प्रयास किया गया, स्पेस लैब की अवधारणा ने विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी जानकारी को केवल पढ़ने के बजाय उसे समझने,सवाल पूछने और उसके पीछे की तकनीक को जानने का अवसर दिया,यह पहल बच्चों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा को शिक्षा के साथ जोड़ा गया है, रॉकेट कैसे उड़ता है,अंतरिक्ष तकनीक किस तरह काम करती है,उपग्रहों का क्या महत्व है और विज्ञान एवं तकनीक भविष्य को किस तरह बदल सकती है–ऐसे विषय विद्यार्थियों के लिए सीखने का नया अनुभव बनते हैं।

साइंस लर्निंग लैब से बदला पढ़ाई का तरीका

कोरिया जिले में साइंस लर्निंग लैब विकसित करने के प्रयास भी शैक्षणिक नवाचार की महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं,इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पाठ्यपुस्तक और रटने की पद्धति तक सीमित रखने के बजाय प्रयोग एवं अनुभव आधारित शिक्षा से जोड़ना है,कक्षा में किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को पढ़ना एक बात है और उसी सिद्धांत को प्रयोग के माध्यम से समझना दूसरी,प्रयोगशाला आधारित शिक्षा बच्चों को यह समझने का अवसर देती है कि किताब में पढ़ाया गया सिद्धांत वास्तविक परिस्थितियों में किस तरह काम करता है,इसी सोच के साथ विद्यालयों में विज्ञान से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया,विद्यार्थियों को प्रयोग करने, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने और वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने के अवसर दिए गए, इससे विज्ञान को केवल परीक्षा का विषय मानने के बजाय उसे आसपास की दुनिया को समझने का माध्यम बनाने की कोशिश हुई।

विज्ञान प्रदर्शनियों से बढ़ी बच्चों की भागीदारी-जिले में विज्ञान प्रदर्शनियों, साइंस सेमिनार और साइंस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ने के प्रयास किए गए,इन गतिविधियों में बच्चों को अपने विचार प्रस्तुत करने,वैज्ञानिक प्रयोगों को समझने और नए विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिला,इस तरह की गतिविधियां विद्यार्थियों में मंच पर अपनी बात रखने का आत्मविश्वास भी विकसित करती हैं,साथ ही किसी समस्या को समझकर उसके समाधान के बारे में सोचने की आदत विकसित होती है, शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भी विज्ञान को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय गतिविधि आधारित बनाने से विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि पैदा होती है। कोरिया में किए जा रहे प्रयास इसी दिशा में दिखाई देते हैं।

एआई,रॉकेट साइंस और 3डी प्रिंटिंग से परिचय-आज की दुनिया तेजी से तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रही है,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,रोबोटिक्स,स्पेस टेक्नोलॉजी और 3डी प्रिंटिंग जैसे क्षेत्र आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार और उद्योग की दिशा बदलने वाले हैं, कोरिया जिले में विद्यार्थियों को इन आधुनिक विषयों से परिचित कराने का प्रयास किया गया,एआई,रॉकेट साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और 3डी प्रिंटिंग जैसे विषयों को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया से जोड़ना इस नवाचार की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है,इसका उद्देश्य बच्चों को भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करना है,शुरुआती उम्र में ही यदि विद्यार्थी इन विषयों के बारे में जानें तो उनके सामने विज्ञान और तकनीक आधारित करियर की संभावनाओं की जानकारी भी विकसित हो सकती है।

वैज्ञानिक सोच विकसित करना बना प्रमुख लक्ष्य-कोरिया के शैक्षणिक नवाचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू केवल विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाना नहीं,बल्कि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है,वैज्ञानिक सोच का अर्थ केवल विज्ञान की किताब पढ़ना नहीं है, सवाल पूछना,किसी तथ्य को तर्क के आधार पर समझना,प्रयोग के माध्यम से परिणाम देखना और समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करना भी वैज्ञानिक सोच का हिस्सा है,स्पेस लैब और साइंस लर्निंग लैब जैसी पहल बच्चों को इसी दिशा में आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकती हैं,इससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा होती है और वे किसी विषय को केवल याद करने के बजाय उसके पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं।

संस्थाओं की सहभागिता ने भी बढ़ाई गतिविधियां-जिले में विज्ञान शिक्षा को मजबूत बनाने में विभिन्न संस्थाओं की सहभागिता भी रही है,रेड क्रॉस सोसाइटी एवं ब्रेकथ्रू साइंस सोसाइटी जैसे संस्थानों की सहभागिता से विज्ञान आधारित गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहयोग मिला,साइंस कॉन्फ्रेंस और अन्य वैज्ञानिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी ने उन्हें अपने स्कूल और कक्षा से बाहर निकलकर व्यापक वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर दिया,इससे बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि के साथ-साथ संवाद, प्रस्तुति और समस्या समाधान जैसी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिला।

राज्य में शैक्षणिक गुणवत्ता में कोरिया का प्रथम स्थान-कोरिया जिले में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी बताया गया है कि जिले ने शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है,विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार, नवाचार आधारित शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक के प्रति रुचि विकसित करने और विद्यालयों में नई गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयासों को इस उपलब्धि से जोड़ा गया है, राष्ट्रीय स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी को मिला सम्मान इस उपलब्धि के साथ कोरिया की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है।

सम्मान केवल अधिकारी का नहीं, पूरी टीम का-जिला शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र गुप्ता ने राष्ट्रीय सम्मान को व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में लेने के बजाय इसे शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षा विभाग की पूरी टीम का सामूहिक प्रयास बताया,उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा कराने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करना भी जरूरी है, यही सोच शिक्षा में नए प्रयोगों और नवाचारों को आगे बढ़ाने का आधार बन सकती है।

दूरस्थ जिले से राष्ट्रीय मंच तक पहुंची पहल-कोरिया जैसे जिले में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इन प्रयोगों की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आधुनिक तकनीक और विज्ञान आधारित सुविधाओं को लेकर आम धारणा अक्सर बड़े शहरों और महानगरों तक सीमित रहती है, लेकिन यदि जिले के विद्यालयों में बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई, 3डी प्रिंटिंग और प्रयोग आधारित विज्ञान शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो यह ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए नए अवसर खोल सकता है,यह पहल बच्चों को यह अहसास भी दिला सकती है कि विज्ञान और तकनीक की दुनिया उनके लिए भी उतनी ही खुली है जितनी किसी बड़े शहर के विद्यार्थी के लिए।

किताब से लैब तक और जिज्ञासा से नवाचार तक-कोरिया में किए गए शैक्षणिक प्रयोगों की सबसे बड़ी खासियत यही दिखाई देती है कि यहां 'क्या पढ़ना है' के साथ-साथ 'कैसे सीखना है' पर भी ध्यान देने का प्रयास किया गया है,स्पेस लैब इसका सबसे रचनात्मक उदाहरण है, जिस अंतरिक्ष को बच्चे अब तक किताबों, तस्वीरों और समाचार चैनलों में देखते थे,उसे स्कूल की लैब के माध्यम से समझने का अवसर मिलना उनके लिए अलग अनुभव है, एक बच्चा जब रॉकेट,अंतरिक्ष या किसी तकनीकी मॉडल को देखकर सवाल करता है तो वही सवाल उसके भीतर सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। यही जिज्ञासा आगे चलकर वैज्ञानिक सोच और नवाचार की नींव बन सकती है।

राष्ट्रीय सम्मान के बाद बढ़ी जिम्मेदारी

जिला शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र गुप्ता को मिला राष्ट्रीय सम्मान कोरिया जिले के लिए गौरव का विषय जरूर है, लेकिन इसके साथ शिक्षा व्यवस्था के सामने आगे की चुनौती भी है, नवाचारों को केवल पुरस्कार तक सीमित रखने के बजाय उन्हें लगातार विकसित करना और अधिक से अधिक विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण होगा,स्पेस लैब, साइंस लर्निंग लैब,विज्ञान प्रदर्शनियां, साइंस कॉन्फ्रेंस और आधुनिक तकनीक से जुड़े विषयों को यदि निरंतरता के साथ विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है तो इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में और व्यापक हो सकता है, कोरिया की यह पहल एक संदेश देती है कि यदि बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को सही दिशा,प्रयोग का अवसर और आधुनिक तकनीक से परिचय मिले,तो दूरस्थ क्षेत्र के स्कूलों से भी विज्ञान और नवाचार की नई कहानी लिखी जा सकती है।

एक नजर में उपलब्धियां

- जिला शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र गुप्ता को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान।
- 3 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में सम्मान समारोह।
- NIEPA द्वारा शैक्षणिक प्रशासन एवं नवाचार के लिए सम्मान।
- वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय सम्मान।
- विद्यालयों में साइंस लर्निंग लैब विकसित करने की पहल।
- स्पेस लैब के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने का प्रयास।
- एआई, रॉकेट साइंस,स्पेस टेक्नोलॉजी और 3डी प्रिंटिंग से विद्यार्थियों का परिचय।
- विज्ञान प्रदर्शनियों,सेमिनार और साइंस कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा।
- रेड क्रॉस सोसाइटी एवं ब्रेकथ्रू साइंस सोसाइटी की सहभागिता।
- शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में कोरिया जिले के राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा।

विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका : शिक्षक राष्ट्र के निर्माता

ब्रह्माकुमारीज के शिक्षा प्रभाग ने आयोजित की संगोष्ठी एवं शिक्षक सम्मान समारोह

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,07 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रभाग,अंबिकापुर द्वारा 'विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका' विषय पर संगोष्ठी एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान,दीप प्रज्ज्वलन, स्वागत नृत्य, नाटिका,गीत एवं संगीत की प्रस्तुतियों के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय,सरगुजा के कुलपति डॉ. राजेन्द्र लखपाले ने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। शिक्षक विद्यार्थियों को ऐसा मार्गदर्शन देता है,जिससे वे आगे चलकर आईएएस,डॉक्टर,इंजीनियर के साथ-साथ अच्छे नागरिक बनते हैं। उन्होंने भारतीय गुरुकुल शिक्षा की विश्वव्यापी प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए शिक्षकों से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने

का आह्वान किया। उन्होंने 'आत्म दीपो भव:' की भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। संयुक्त संचालक सरगुजा संभाग डॉ. राजेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2037 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शिक्षक को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निर्धारित करनी होगी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा ने कहा कि बच्चों की गतिविधियों के साथ उनके संस्कारों पर ध्यान देना भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आधुनिक तकनीक के दौर में बच्चों में संस्कार और माता-पिता के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखने पर भी उन्होंने जोर दिया।

शिक्षा के साथ आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर : ब्रह्माकुमारीज सेवा केंद्र संचालिका एवं सरगुजा संभाग राजयोगिनी बीके विद्या दीदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए ज्ञानवान नागरिक,संस्कारवान युवा, ईमानदार नेतृत्व और चरित्रवान समाज आवश्यक है। शिक्षा में आध्यात्मिकता का समावेश विद्यार्थियों को मूल्यवान एवं चरित्रवान बनाने में सहायक है। उन्होंने आध्यात्मिकता को अपनी वास्तविक पहचान एवं जीवन के उद्देश्य को समझने

का माध्यम बताया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को राजयोग का अभ्यास कराया गया तथा सामूहिक नशा मुक्ति प्रतिज्ञा भी दिलाई गई।

इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर.एन. खरे ने शिक्षक को अहंकार से दूर रहते हुए विनम्रता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करने की बात कही। डाईट प्राचार्य के.सी. गुप्ता ने कहा कि शिक्षक जब विद्यार्थियों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और उन्हें अपने बच्चों के समान मानते हैं,तभी उनमें संस्कारों का विकास होता है। श्री साईं बाबा कॉलेज के प्राचार्य राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षा से महान कुछ भी नहीं है। शिक्षक ही विद्यार्थियों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि तकनीक जानकारी दे सकती है, लेकिन संवेदनशीलता और मानवीय भावनाएं विकसित करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि शिक्षक का सम्मान किसी एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा का विशेष महत्व रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य आर.जे. पाण्डेय ने कहा कि तकनीकी साधनों के

बढ़ते प्रभाव के बीच शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बढ़ती दूरी को कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा के साथ जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

शिक्षकों का किया सम्मान : कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं राजकीय पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्यांगना सृष्टि मिश्रा ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों को सम्मान पट्टिका, श्रीफल, प्रमाण-पत्र एवं ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक देवेंद्र नाथ दुबे को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वहीं गिरीश गुप्ता को साक्षर भारत अभियान में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मंगल पाण्डेय एवं कवि-साहित्यकार संतोष दास 'सरल' की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्माकुमारी प्रतिमा बहन ने किया। इस अवसर पर अंबिकापुर के विभिन्न शासकीय एवं निजी विद्यालयों-महाविद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

हाथियों के आतंक में बेघर होते परिवार,आखिर कब जागेगा वन विभाग?

जनकपुर क्षेत्र में बढ़ा मानव-हाथी संघर्ष : थोड़गी के हतवारी पारा में तीन मकान क्षतिग्रस्त,ग्रामीणों में दहशत का माहौल

राजन पाण्डेय

एमसीबी,07 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

जनकपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों की बढ़ती आवाजाही अब ग्रामीणों के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है, हाथियों का झुंड अब केवल खेतों और फसलों तक ही सीमित नहीं रह गया है,बल्कि आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों के घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। थोड़गी गांव के हतवारी पारा में हाथियों के दल ने तीन मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, घटना के बाद प्रभावित परिवारों के सामने अपने घर और सामान की सुरक्षा के साथ-साथ रहने की समस्या भी खड़ी हो गई है। घटना के बाद सामने आई तस्वीरें मानव-हाथी संघर्ष की भयावह स्थिति को बयां कर रही हैं। कहीं घर की दीवारें टूटी हैं तो कहीं छत और घरेलू सामान बिखरा पड़ा है। जिन मकानों में परिवार सामान्य दिनों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, वहां अब हाथियों के पहुंचने के बाद डर और अनिश्चितता का माहौल है, ग्रामीणों के लिए यह केवल संपत्ति के नुकसान की घटना नहीं,बल्कि रात होते ही सिर पर मंडराने वाले खतरे का एहसास भी है।

खेतों से घरों तक पहुंचा हाथियों का आतंक-जनकपुर और आसपास के वनांचल क्षेत्रों में हाथियों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है,जंगल से लगे गांवों में हाथियों के आने और फसलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं,ग्रामीण भी वन्यजीवों के साथ रहने के आदी हैं और हाथियों से दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं,लेकिन जब हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर सीधे आबादी वाले हिस्सों और घरों तक पहुंचने लगे, तो स्थिति काफी गंभीर हो जाती है,थोड़गी के हतवारी पारा की घटना ने इसी बढ़ते संघर्ष की तस्वीर सामने रखी है,तीन मकानों का क्षतिग्रस्त होना यह संकेत देता है कि हाथियों की आवाजाही अब ग्रामीण बस्तियों के बेहद करीब तक पहुंच रही है,ऐसे में सवाल केवल फसल बचाने का नहीं,बल्कि ग्रामीणों की जान-माल की सुरक्षा का भी है।

ग्रामीणों का सवाल...पहले से क्यों नहीं मिलती सूचना?-हाथियों की गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों के बीच सबसे बड़ा सवाल समय पर सूचना और चेतावनी व्यवस्था को लेकर है। यदि किसी इलाके में हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है तो संवेदनशील गांवों में समय रहते इसकी जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है, ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें पहले से पता हो कि हाथियों का झुंड किस दिशा में बढ़ रहा है, तो वे अपने परिवार और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी कर सकते हैं,इसी तरह वन विभाग की टीम भी संवेदनशील स्थानों पर पहले से निगरानी बढ़ा सकती है,यहीं से वन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है,हाथियों की लोकेशन पर नजर रखने, संभावित मार्गों की पहचान करने,ग्रामीणों को अलर्ट करने और जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार सक्रिय निगरानी तंत्र जरूरी है।

घटना के बाद राहत जरूरी,लेकिन रोकथाम उससे भी जरूरी-वन्यजीवों से होने वाले नुकसान के बाद प्रभावित परिवारों को राहत और नियमानुसार मुआवजा मिलना जरूरी है, क्षतिग्रस्त मकानों का आकलन,फसल नुकसान का सर्वे और पात्र परिवारों को निर्धारित सहायता समय पर मिले,यह प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन केवल नुकसान का आकलन और मुआवजा मानव-हाथी संघर्ष का स्थायी समाधान नहीं है,सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए पहले से क्या तैयारी की जा रही है,हाथियों के पारंपरिक आवागमन वाले रास्तों की पहचान,संवेदनशील गांवों की सूची तैयार करना,नियमित गश्त, ग्रामीणों को तत्काल सूचना देने की व्यवस्था और प्रशिक्षित वन अमले की तैनाती जैसे कदम इस संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

वन्यजीव संरक्षण और इंसानी सुरक्षा में संतुलन जरूरी- हाथी हमारे वन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उनके संरक्षण से किसी भी तरह समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारी के साथ उन ग्रामीणों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो जंगलों के आसपास पीढ़ियों से रह रहे हैं, मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ता टकराव केवल वन विभाग की समस्या नहीं,बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी हैं। इसलिए वन विभाग,स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण समुदाय के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है,ग्रामीणों को यह भी बताया जाना जरूरी है कि हाथियों के गांव में प्रवेश की स्थिति में क्या करना चाहिए और किन गतिविधियों से बचना चाहिए, जागरूकता और त्वरित सूचना तंत्र के अभाव में कई बार ग्रामीण अनजाने में खुद को खतरे में डाल सकते हैं।

टूटे मकान पूछ रहे हैं कई सवाल-थोड़गी के हतवारी पारा में क्षतिग्रस्त तीन मकान अब सिर्फ नुकसान की तस्वीर नहीं हैं,वे मानव-हाथी संघर्ष की उस चुनौती की ओर इशारा कर रहे हैं,जो धीरे-धीरे गंभीर होती जा रही है,सवाल यह नहीं है कि हाथी जंगल से गांव तक क्यों आ रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब हाथियों की गतिविधियों की जानकारी पहले से रहती है,तब संवेदनशील गांवों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त और प्रभावी व्यवस्था कितनी मजबूत है, क्या हाथियों की निगरानी के लिए पर्याप्त अमला और संसाधन उपलब्ध हैं? क्या संवेदनशील गांवों में समय पर चेतावनी पहुंच रही है? क्या प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है? और सबसे अहम–क्या हर घटना के बाद की कार्रवाई के बजाय ऐसी घटनाओं को रोकने की दीर्घकालीन योजना जमीन पर दिखाई दे रही है? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं,क्योंकि जंगल और गांव की दूरी भले कम हो रही हो, लेकिन इंसान और हाथी के बीच टकराव की कीमत किसी परिवार को अपना घर,अपनी फसल या इससे भी बढ़कर अपनी जिंदगी गंवाकर नहीं चुकानी चाहिए।

रात होते ही ग्रामीणों में बढ़ जाती है दहशत

हाथियों की मौजूदगी के कारण ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता रात के समय बढ़ जाती है,दिन ढलते ही लोगों को अपने आसपास हाथियों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहना पड़ता है,जिन परिवारों के घर हाथियों की आवाजाही वाले इलाकों में हैं,उनके लिए हर आहट चिंता का कारण बन जाती है,ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के अचानक गांव में पहुंचने की स्थिति में उन्हें अपने परिवार और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की चिंता रहती है,कई बार लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालात में घर में रखा अनाज,घरेलू सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं भी असुरक्षित हो जाती हैं,सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ग्रामीणों के पास हाथियों से निपटने का कोई सुरक्षित साधन नहीं होता,हाथियों को भगाने की कोशिश कई बार ग्रामीणों के लिए ही जोखिम पैदा कर सकती है,इसलिए विशेषज्ञ और वन विभाग भी आमतौर पर हाथियों से दूरी बनाए रखने और प्रशिक्षित अमले की निगरानी में कार्रवाई की सलाह देते हैं।

फसल नुकसान से पहले ही परेशान हैं किसान

हाथियों का आतंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है, क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर हैं, किसान बड़ी मेहनत और लागत से फसल तैयार करते हैं, ऐसे में हाथियों द्वारा खेतों में घुसकर फसल रौंदने या नष्ट करने से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है,खेती की बढ़ती लागत,मौसम की अनिश्चितता और बाजार से जुड़ी चुनौतियों के बीच यदि तैयार फसल हाथियों की चपेट में आ जाए तो ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है,मकान और फसल दोनों के नुकसान की स्थिति में प्रभावित परिवारों के सामने आर्थिक संकट और भी गहरा हो सकता है।

अब कागजी कार्रवाई नहीं, जमीन पर दिखे तैयारी

थोड़गी की घटना के बाद जरूरत है कि वन विभाग संवेदनशील क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का आकलन करे और हाथियों की आवाजाही वाले गांवों के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करे, प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत के साथ मकान और फसल नुकसान का निष्पक्ष सर्वे कराया जाए तथा पात्रता के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाए, साथ ही हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने,समय पर सूचना देने और ग्रामीणों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए,क्योंकि मानव-हाथी संघर्ष का समाधान केवल हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने या घटना के बाद मुआवजा देने से नहीं होगा,इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें वन्यजीव भी सुरक्षित रहें और जंगल की सीमा से लगे गांवों में रहने वाले परिवार भी आज थोड़गी में तीन घरों की दीवारें टूटी हैं, जरूरत इस बात की है कि इस घटना को एक और सामान्य वन्यजीव घटना मानकर भुला न दिया जाए, यदि समय रहते ठोस कदम उठाए गए तो भविष्य में बड़े नुकसान को टाला जा सकता है। वरना अगली बार सवाल केवल टूटे घरों का नहीं,किसी इंसानी जिंदगी का भी हो सकता है।

सात दिन में संवरा कोटाडोल पुलिया,आवागमन बहाल-लोडेड ट्रकों पर रोक,एक समय में एक चार पहिया वाहन की अनुमति

- कोटाडोल पुलिया खुली...लेकिन प्रतिबंध जारी: एक समय में एक चारपहिया वाहन ही गुजर सकेगा
- सात दिन में पूरी हुई अस्थायी मरम्मत,सुरक्षा के मद्देनजर लोडेड ट्रकों का आवागमन रहेगा पूरी तरह प्रतिबंधित

-संवाददाता-
एमसीबी,07 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त कोटाडोल पुलिया को अस्थायी मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद आज सोमवार से आवागमन के लिए खोल दिया गया है। यह पुलिया कोटाडोल से खिरकी के मध्य मुख्य मार्ग पर स्थित है और इसके खुलने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा। भारी वर्षा के कारण पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सात दिवस के भीतर अस्थायी मरम्मत कार्य पूर्ण किया गया। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पुलिया से वाहनों का आवागमन पुनः प्रारंभ कर दिया गया है,हालांकि,पुलिया की सुरक्षा एवं संरचनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल आवागमन पर दो महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे। एक समय में पुलिया से केवल एक चारपहिया वाहन को ही गुजरने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के लोडेड ट्रक का पुलिया से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने तथा पुलिया से गुजरते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है, वाहन चालकों से यह भी कहा गया है कि वे जल्दबाजी न करें और पुलिया पर निर्धारित नियमों के अनुसार ही आवागमन करें,ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अप्रिय स्थिति से बचा जा सके,प्रशासन द्वारा क्षतिग्रस्त पुलिया की स्थिति को देखते हुए अस्थायी मरम्मत के माध्यम से आवागमन बहाल किया गया है, सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए प्रतिबंधों के साथ यातायात संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

सूरजपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल,8 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना

6 निरीक्षकों और 2 उप निरीक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी,थाना प्रभारियों के बदलाव से पुलिसिंग व्यवस्था में आएगा बदलाव

-संवाददाता-
सूरजपुर,07 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

जिले की कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए 8 पुलिस अधिकारियों की नवीन पदस्थापना का आदेश जारी किया है, जारी आदेश में 6 निरीक्षकों और 2 उप निरीक्षकों को वर्तमान पदस्थापना से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, फेरबदल के तहत कई महत्वपूर्ण थानों के प्रभारी बदले गए हैं, जबकि एक निरीक्षक को रक्षित केंद्र भेजा गया है,पुलिस प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं,साथ ही आमद-रवानगी की सूचना पुलिस कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

प्रतापपुर, प्रेमनगर,ओड़गी और विश्रामपुर के थाना प्रभारी बदले-स्थानांतरण आदेश के तहत निरीक्षक नरेंद्र सिंह को थाना प्रभारी प्रतापपुर से हटाकर थाना प्रभारी प्रेमनगर की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं निरीक्षक दिनेश पुरेना,जो वर्तमान में थाना प्रभारी ओड़गी के रूप में पदस्थ थे,उन्हें थाना प्रभारी प्रतापपुर बनाया गया है,इसी क्रम में निरीक्षक विकास देशमुख को थाना प्रभारी प्रेमनगर से हटाकर थाना प्रभारी विश्रामपुर पदस्थ किया गया है,वहीं निरीक्षक अलरिक लकड़ा को थाना प्रभारी सूरजपुर के पद से हटाकर थाना प्रभारी ओड़गी की जिम्मेदारी सौंपी गई है,थाना विश्रामपुर की कमान संभाल रहे निरीक्षक रूपेश कुंतल एक्का को अब रक्षित केंद्र सूरजपुर भेजा गया है, इसके साथ ही रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक प्रह्लाद कुमार यादव को थाना प्रभारी सूरजपुर की जिम्मेदारी दी गई है,इस बदलाव के साथ जिले के कई प्रमुख थानों में नए थाना प्रभारियों की तैनाती हो गई है।

दो उप निरीक्षकों की भी बदली जिम्मेदारी-थाना प्रभारियों के साथ-साथ चौकी और थाना स्तर पर पदस्थ दो उप निरीक्षकों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है, आदेश के अनुसार सउनि योगेन्द्र जायसवाल, जो वर्तमान में चौकी प्रभारी बसदेई के रूप में कार्यरत थे,उन्हें थाना प्रतापपुर पदस्थ किया गया है, वहीं सउनि रघुवंश सिंह,जो प्रभारी जिविशा के रूप में पदस्थ थे,उन्हें चौकी प्रभारी बसदेई की जिम्मेदारी सौंपी गई है,इस तरह जिले में थाना और चौकी स्तर पर पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

तत्काल प्रभाव से संभालना होगा नया प्रभार-पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही अधिकारियों को अपनी आमद और रवानगी की सूचना पुलिस कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, प्रशासनिक स्तर पर जारी इस आदेश के बाद संबंधित थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

पहले भी हो चुका है थाना-चौकी स्तर पर फेरबदल-गौरतलब है कि जिले में हाल के दिनों में भी थाना एवं चौकी स्तर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। अब एक बार फिर 8 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना से पुलिस विभाग में व्यापक स्तर पर जिम्मेदारियों का पुनर्विन्यास हुआ है, लगातार किए जा रहे प्रशासनिक फेरबदल को पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर पर जिन थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और आम जनता से सीधे जुड़ी पुलिसिंग की जिम्मेदारी अधिक होती है, वहां थाना प्रभारी की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।

अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था पर रहेगा फोकस- प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, लंबित मामलों के निराकरण तथा आम लोगों के बीच पुलिस की पहुंच और सक्रियता को बेहतर बनाना माना जा रहा है, नए थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालने के बाद स्थानीय परिस्थितियों,अपराध के स्वरूप और संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन कर पुलिसिंग की प्राथमिकताएं तय करेंगे,वहीं अधिकारियों के अनुभव का उपयोग अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा।

एक नजर में नई पदस्थापना

अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
निरीक्षक नरेंद्र सिंह	थाना प्रभारी प्रतापपुर	थाना प्रभारी प्रेमनगर
निरीक्षक दिनेश पुरेना	थाना प्रभारी ओड़गी	थाना प्रभारी प्रतापपुर
निरीक्षक विकास देशमुख	थाना प्रभारी प्रेमनगर	थाना प्रभारी विश्रामपुर
निरीक्षक अलरिक लकड़ा	थाना प्रभारी सूरजपुर	थाना प्रभारी ओड़गी
निरीक्षक रूपेश कुंतल एक्का	थाना प्रभारी विश्रामपुर	रक्षित केंद्र सूरजपुर
निरीक्षक प्रहलाद कुमार यादव	रक्षित केंद्र सूरजपुर	थाना प्रभारी सूरजपुर
सउनि योगेन्द्र जायसवाल	चौकी प्रभारी बसदेई	थाना प्रतापपुर
सउनि रघुवंश सिंह	प्रभारी जिविशा	चौकी प्रभारी बसदेई

कुल 8 अधिकारियों के इस फेरबदल से जिले के प्रमुख थाना क्षेत्रों में पुलिस नेतृत्व की नई टीम सामने आई है। अब इन अधिकारियों के सामने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता के बीच पुलिस की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी।

स्मार्ट मीटरों में अधिक बिजली खपत की शिकायतों पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

राजन पाण्डेय

कोरिया,07 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेश में स्मार्ट मीटरों से जुड़ी अत्यधिक बिजली खपत की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है,उन्होंने शिकायतों की जांच कराने और प्रभावित उपभोक्ताओं के संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई के निर्देश जारी करने की मांग की है,मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में डॉ. महंत ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों और नगरीय निकायों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उनके अनुसार,स्मार्ट मीटर स्थापित होने के बाद आम उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि की शिकायतें सामने आ रही हैं।

टेस्ट मीटर से अधिक खपत का मामला भी उठाया-डॉ. महंत ने अपने

पत्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ अभियंता, कोरिया के पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की है,इसमें कोरिया जिला निवासी भावना गुप्ता द्वारा बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायत और टेस्ट मीटर लगाने का निवेदन किए जाने का उल्लेख है, पत्र के अनुसार, शिकायत पर विद्युत विभाग द्वारा टेस्ट मीटर लगाया गया। इसके बाद समान समयांतराल में की गई तुलना में स्मार्ट मीटर की खपत टेस्ट मीटर से अधिक पाई गई। डॉ. महंत ने इस मामले को स्मार्ट मीटरों की कार्यप्रणाली की जांच की आवश्यकता के उदाहरण के रूप में मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है, उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि कई उपभोक्ताओं ने पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की तुलना में नए स्मार्ट मीटरों में बिजली की खपत कई गुना बढ़ने की शिकायत की है, कुछ मामलों में घर के मुख्य विद्युत उपकरण बंद रखने के बावजूद मीटर की रीडिंग बढ़ने का दावा भी किया गया है, डॉ. महंत ने इन शिकायतों के आधार पर स्मार्ट मीटरों में तकनीकी खामी या सॉफ्टवेयर संबंधी गड़बड़ी की आशंका जताई है,नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आम जनता, विशेषकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवार,पहले से ही बढ़ी हुई बिजली दरों और महंगाई की मार झेल रहे हैं,ऐसे में स्मार्ट मीटरों से संबंधित शिकायतों का समाधान नहीं होने पर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

जांच और मीटर बदलने की मांग- डॉ. महंत ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अत्यधिक बिजली खपत की प्रमाणित शिकायतें करने वाले उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर तत्काल प्रभाव से बदले जाएं। साथ ही,प्रदेश स्तर पर स्मार्ट मीटरों की खरीद, प्रोग्रामिंग तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सत्यता में आ रही खामियों की जांच उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति या प्रयोगशाला से कराई जाए, उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निष्पक्ष परीक्षण कराकर उपभोक्ताओं को राहत दी जानी चाहिए।

CMYK

गर्लफ्रेंड समरीन के बर्थडे पर रोमांटिक हुए अर्शदीप सिंह

खुलम खुला लुटाया जान पर प्यार,बोले...मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं...

क्रिकेटर अर्शदीप सिंह इन दिनों अपने लेडी लव पर प्यार लुटाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने गर्लफ्रेंड के बर्थडे को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह इन दिनों अपने खेल के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में हैं। क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर को जन्मदिन की बधाई देते हुए कुछ खास तस्वीरें साझा कीं। पोस्ट में दोनों के साथ बिताए निजी पलों की कई झलकियां दिखाई दीं। छुट्टियों के दौरान खींची गई तस्वीरों से लेकर साथ बिताए कुछ सहज और खुशनुमा पलों तक, अर्शदीप ने तस्वीरों के जरिए अपने रिश्ते की झलक फैंस के साथ साझा की।

तस्वीरों के साथ लिखा दिल छू लेने वाला संदेश

अर्शदीप ने तस्वीरों का एक कैरोसेल पोस्ट किया, जिसमें उनके और समरीन के साथ बिताए अलग-अलग पलों को शामिल किया गया था। उन्होंने हर तस्वीर के साथ अलग अंदाज में अपनी भावनाएं जाहिर कीं। हालांकि पोस्ट में किसी औपचारिक या लंबे संदेश के बजाय तस्वीरों को ज्यादा महत्व दिया गया। एक तस्वीर साझा करते हुए अर्शदीप ने समरीन को जन्मदिन की शुभकामना दी और उन्हें अपना खास साथी बताया। उन्होंने लिखा,हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मेरी क्रेजी, स्मार्ट,मेच्योर और खूबसूरच पार्टनर इस संदेश में क्रिकेटर ने समरीन के लिए अपने लगाव के साथ-साथ उनकी समझदारी और खूबसूरती की भी तारीफ की। पोस्ट की आखिरी तस्वीर के साथ अर्शदीप ने अपने अंदाज में प्यार का इजहार किया। उन्होंने लिखा, आई लव यू सो मच। उनका यह चुलबुला संदेश भी सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का हिस्सा बन गया।

फैंस ने लुटाया प्यार

अर्शदीप की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कई लोगों ने समरीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, जबकि कुछ यूजर्स ने दोनों की तस्वीरों पर प्यार जताया। कपल की तस्वीरों को लेकर फैंस के बीच पहले से ही दिलचस्पी देखने को मिलती रही है और इस पोस्ट ने उसे और बढ़ा दिया। पिछले कुछ महीनों में समरीन अर्शदीप के सोशल मीडिया पोस्ट में पहले की तुलना में ज्यादा नजर आने लगी हैं। दोनों की तस्वीरों और सोशल मीडिया गतिविधियों के कारण उनके रिश्ते को लेकर फैंस की उत्सुकता भी बढ़ी है।

मैचिंग टैटू ने भी खींचा था ध्यान

अर्शदीप और समरीन के रिश्ते की चर्चा उस समय भी तेज हुई थी, जब दोनों के मैचिंग टैटू सामने आए थे। अर्शदीप ने अपने ऊपरी बाजू पर SK टैटू बनवाया है। खास बात यह है कि यह अक्षर समरीन की हैंडराइटिंग में लिखे गए हैं। वहीं समरीन ने AS टैटू बनवाया है,जिसे अर्शदीप की लिखावट में तैयार किया गया है। दोनों टैटू में एक छोटा लाल दिल भी शामिल है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस ने इन टैटू को दोनों के रिश्ते से जोड़कर देखा और इसे उनके बीच के खास जुड़ाव का संकेत बताया।

कौन हैं समरीन कौर?

समरीन कौर को सार्वजनिक तौर पर पहचान मुख्य रूप से अर्शदीप सिंह के साथ उनके रिश्ते के कारण मिली है। पिछले कुछ समय में वह क्रिकेटर की सोशल मीडिया पोस्ट में कई बार नजर आई हैं। हालांकि अर्शदीप की तरह वह क्रिकेट या मनोरंजन जगत का कोई बड़ा सार्वजनिक चेहरा नहीं हैं। दोनों धीरे-धीरे अपने रिश्ते से जुड़े पलों को सोशल मीडिया पर साझा करते रहे हैं। यही वजह है कि अर्शदीप के फैंस अब समरीन से जुड़ी पोस्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उनके साथ की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ जाती हैं।

सोशल मीडिया पर बढ़ी रिश्ते की झलक

अर्शदीप और समरीन की तस्वीरों में किसी बड़े सार्वजनिक ऐलान के बजाय निजी पलों की झलक ज्यादा दिखाई देती है। कभी दोनों छुट्टियों के दौरान साथ नजर आते हैं तो कभी साधारण पलों को तस्वीरों में कैद करते हैं। इस तरह उनकी सोशल मीडिया मौजूदगी धीरे-धीरे उनके रिश्ते को प्रशंसकों के सामने अधिक स्पष्ट करती जा रही है। समरीन के जन्मदिन पर अर्शदीप की नई पोस्ट भी इसी सिलसिले का हिस्सा रही। उन्होंने किसी औपचारिक शुभकामना संदेश के बजाय तस्वीरों और छोटे-छोटे कैप्शन के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

परिणीति चोपड़ा की मिस्ट्री थ्रिलर शक : ट्रस्ट नो वन की रिलीज डेट तय,सितंबर में देगी दस्तक

परिणीति चोपड़ा नेटफ्लिक्स की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज **शक:** ट्रस्ट नो वन से अपना ओटीटी डेब्यू करने जा रही हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अब इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। परिणीति चोपड़ा मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज **शक:** ट्रस्ट नो वन के साथ ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। यह एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, जो अपने खोए हुए बच्चे की तलाश कर रही एक मां की कहानी पर आधारित है। नेटफ्लिक्स की यह सीरीज सितंबर में रिलीज होगी और इसमें जेनिफर विंगेट, सोनी राजदान, ताहिर राज भसीन और सुमीत व्यास जैसे कई कलाकार शामिल हैं। परिणीति चोपड़ा ने द गर्ल ऑन द ट्रेन और अमर सिंह चमकीला जैसी डायरेक्ट-टू-डिजिटल रिलीज वाली फिल्मों में भी काम किया है। अब परिणीति अपनी नई वेब सीरीज से ओटीटी पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं।

शक : ट्रस्ट नो वन कब होगी रिलीज

मेकर्स ने सोमवार को घोषणा की कि शक- ट्रस्ट नो वन नाम की यह सीरीज 24 सितंबर को रिलीज होगी। इसे एक दिलचस्प मिस्ट्री थ्रिलर बताया गया है,जो अपने लापता बच्चे की तलाश में जुटी एक मां की नौ साल की जद्दोजहद पर आधारित है। रेन्सिल डी सिल्वा और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा द्वारा बनाए गए और रेन्सिल डी सिल्वा द्वारा निर्देशित इस शो को एल्केमी फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। यह शो भरोसा और शक,सहज-बुद्धि और सच्चाई, प्यार और जुनून के बीच की बारीक रेखा को दिखाता है। इस शो की मुख्य भूमिका में परिणीति चोपड़ा हैं और यह

उनके लिए वेब सीरीज की दुनिया में पहला कदम भी है।

रेन्सिल डीसिल्वा का नेटफ्लिक्स पर डेब्यू

शक : ट्रस्ट नो वन को रेन्सिल डीसिल्वा और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने बनाया है और डी सिल्वा ने ही इसे डायरेक्ट भी किया है। इसे एल्केमी फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। यह सीरीज डी सिल्वा का नेटफ्लिक्स पर डेब्यू है। फिल्ममेकर ने पहले फिल्मों और टेलीविजन में काम किया है और शक के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक मिस्ट्री-बेस्ड कहानी लेकर आ रहे हैं। सीरीज के बारे में बात करते हुए डी सिल्वा ने कहा कि कहानी अनसर्टेनिटी पर आधारित है, जिसमें खुलासों से और भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने एक मां की नौ साल की खोज को थ्रिलर में एक अहम इमोशनल पहलू भी बताया। सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा, जो क्रिएटर और प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं। उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है। त्रिभंग, महाराज और इक्का के बाद नेटफ्लिक्स के साथ यह उनका चौथा कोलेबोरेशन है।

शक : ट्रस्ट नो वन की कास्ट

इस सीरीज में परिणीति चोपड़ा के साथ कई कलाकार नजर आएंगे। इस सीरीज में जेनिफर विंगेट,सोनी राजदान,ताहिर राज भसीन,हरलीन सेठी,अनूप सोनी, ध्रुव चौधरी और सुमित व्यास कास्ट का हिस्सा हैं। कहानी की शुरुआत कई सवाल और संभावनाएं छोड़ती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि क्या मां के करीबी लोगों पर सच में भरोसा किया जा सकता है।

शक : ट्रस्ट नो वन कब-कहां देखें

शक :ट्रस्ट नो वन नेटफ्लिक्स की आने वाली वेब सीरीज का टाइटल है,जो 24 सितंबर 2026 को इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। यह परिणीति चोपड़ा की पहली वेब सीरीज है, जो एक गायब बच्चे की मिस्ट्री की कहानी को भरोसे और पेरेंटहुड की थीम के साथ जोड़ती है।

सच्ची घटना से प्रेरित ये मर्डर मिस्ट्री फिल्म खड़े कर देगी रोंगटे

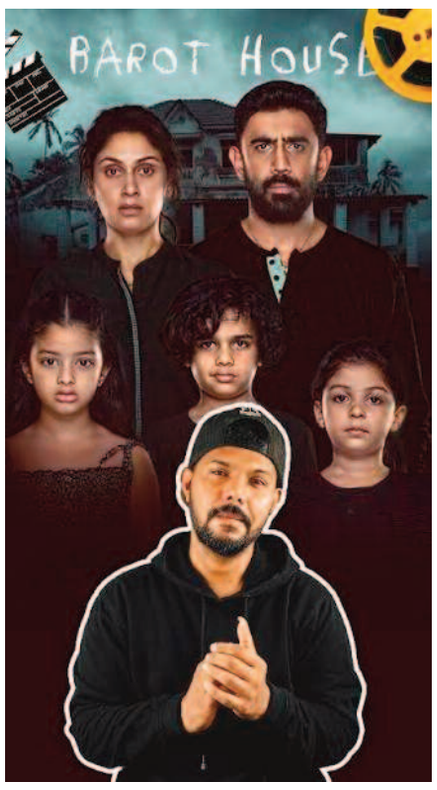

अगर आप क्राइम थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री फिल्मों के शौकीन हैं और ऐसी कहानी तलाश रहे हैं जो आखिरी मिनट तक आपको स्क्रीन से बांधे रखे, तो जी-5 की बरोट हाऊस आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती है। यह फिल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित बताई गई है और एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाती है, जिसकी खुशहाल जिंदगी अचानक हुए एक खौफनाक कत्ल के बाद पूरी तरह बदल जाती है। साल 2019 में रिलीज हुई इस जी-5 बरोट हाऊस फिल्म में अमित साध और मंजरी फडनीस प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी जितनी आगे बढ़ती है, हत्या के पीछे छिपा रहस्य उतना ही उलझता जाता है। शक एक किरदार से दूसरे किरदार की ओर घूमता है और कहानी दर्शकों को लगातार सवाल करने पर मजबूर करती है।

खुशहाल परिवार में अचानक मचता है मातम

कहानी अमित बरोट और उनकी पत्नी भावना बरोट के परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। परिवार अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन अचानक उनकी एक बेटी की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। बेटी की मौत पूरे परिवार को तोड़कर रख देती है। इसके बाद मामला और भयावह होता जाता है। परिवार अभी पहले सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाता कि दूसरी घटना कहानी को ऐसा मोड़ देती है, जिसके बाद परिवार के लोगों से लेकर आसपास मौजूद लोगों तक पर शक गहराने लगता है।

आखिर कातिल कौन?

बरोट हाऊस की खासियत इसकी मर्डर मिस्ट्री है। जांच आगे बढ़ने के साथ कई लोगों पर शक जाता है। कभी शक परिवार के मुखिया अमित पर पहुंचता है तो कभी पड़ोसी और परिवार से जुड़े दूसरे किरदार संदेह के घेरे में आते हैं। फिल्म धीरे-धीरे दर्शकों के सामने ऐसे संकेत रखती है, जिनसे कातिल का अंदाजा लगाना आसान नहीं रहता। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परिवार के भीतर छिपे पहलू सामने आने लगते हैं और माहौल ज्यादा गंभीर होता जाता है।

वास्तविक घटना से प्रेरित है कहानी

फिल्म को वास्तविक घटनाओं से प्रेरित बताया गया है। जी-5 के मुताबिक कहानी अमित और भावना बरोट के परिवार पर केंद्रित है, जहां दो बच्चियों की रहस्यमय तरीके से हत्या होने के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। फिल्म इस घटना को मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री के रूप में प्रस्तुत करती है। यही रियल लाइफ कनेक्शन इसकी कहानी को और ज्यादा गंभीर बनाता है। हालांकि, फिल्मी कहानी में नाटकीय प्रस्तुति भी शामिल है, इसलिए इसे वास्तविक मामले का हूबहू दस्तावेज मानने के बजाय उससे प्रेरित फिल्म के तौर पर देखना उचित होगा।

अमित साध की एक्टिंग बढ़ाती है सस्पेंस

फिल्म में अमित साध ने अमित बरोट का किरदार निभाया है, जबकि मंजरी फडनीस उनकी पत्नी भावना की भूमिका में हैं। दोनों के अभिनय के साथ बाल कलाकारों की भूमिकाएं भी कहानी में अहम हैं। खासकर परिवार के भीतर बढ़ता डर, एक-दूसरे पर शक और लगातार बदलती परिस्थितियां फिल्म के सस्पेंस को बनाए रखती हैं। कहानी में पारिवारिक रिश्तों के साथ मनोवैज्ञानिक पहलू भी शामिल किए गए हैं। लंबी फिल्म नहीं, सीधे मुद्दे पर आती है कहानी अगर आप ढाई-तीन घंटे की लंबी फिल्म देखने के मूड में नहीं हैं तो बरोट हाऊस एक विकल्प हो सकती है। फिल्म करीब 90 मिनट से भी कम समय में अपनी कहानी समेटती है। इसकी कहानी सीधे मुख्य घटना पर आती है और फिर मर्डर मिस्ट्री के जरिए आगे बढ़ती है। इसमें पारंपरिक हॉरर फिल्म जैसे भूत-प्रेत नहीं हैं। डर कहानी की परिस्थितियों, हत्याओं के रहस्य और किरदारों के व्यवहार से पैदा होता है। इसलिए साइकोलॉजिकल क्राइम और मर्डर मिस्ट्री पसंद करने वाले दर्शकों को यह ज्यादा आकर्षित कर सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान

मेलबर्न,07 सितम्बर 2026। ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका दौरे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मेजबान साउथ अफ्रीका ने ओडीआई सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। टीम की कमान टेम्बा बावुमा के हाथों में होगी,जबकि तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जी की ओडीआई टीम में वापसी हुई है। कोएत्जी आखिरी बार 2023 ओडीआई वर्ल्ड के दौरान 50 ओवर के प्रारूप में साउथ अफ्रीका की ओर से खेलते हुए नजर आए थे।

25 साल के कोएत्जी को ओटनील बार्टमैन, क्रेना मफाका, लुंगी एंगिडी के साथ पेस अटैक की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश और मार्को येनसन भी टीम को अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प देंगे। स्पिन विभाग में ब्योर्न फोर्टुइन और केशव महाराज को जगह मिली है। फोर्टुइन फिलहाल नामीबिया दौरे पर साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी कर रहे हैं। स्टार बल्लेबाज एडेन मारक्रम दूसरे और तीसरे ओडीआई के लिए उपलब्ध रहेंगे। टॉप आर्डर में क्विंटन डी कॉक, रयान रिकेलटन और टोनी डी जोरजी विकल्प होंगे। वहीं मैथ्यू ब्रीट्जके, डेविड

मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान किया था।

30 सितंबर को सीरीज का समापन

ओडीआई सीरीज के तीनों मुकाबले साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मैच 24 सितंबर को डरबन के हॉलीवुडबेट्स किंग्समीड स्टेडियम में होगा। इसके बाद 27 सितंबर को जोहान्सबर्ग के डीपी वर्ल्ड वांडरर्स स्टेडियम में दूसरा ओडीआई खेला जाएगा। यह मुकाबला पिंक डे के रूप में आयोजित किया जाएगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 30 सितंबर को पोटचेफस्ट्रम के एनडब्ल्यूसी ओवल में होगा। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की पिछली भिड़ंत 2023 में साउथ अफ्रीकी धरती पर हुई थी। उस पांच मैचों की ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती दो मुकाबले जीते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली थी।

रबाडा नहीं होंगे सीरीज का हिस्सा

साउथ अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू समर की शुरुआत करना रोमांचक है। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले ह्यष्ठठ्ठ वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज टीम कॉम्बिनेशन और खिलाडियों की भूमिकाएं तय करने की दिशा में अहम कदम होगी। कॉनराड ने बताया कि टीम मिडिल ऑर्डर में ऐसा संतुलन चाहती है जो जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सके,लेकिन दबाव की स्थिति में पारी को संभालकर लंबा भी खींच सके। हालांकि,चोट के कारण तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। कोच के मुताबिक,उनकी गैरमौजूदगी दूसरे गेंदबाजों के लिए खुद को साबित करने का मौका है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम : टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन,कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके,गेराल्ड कोएत्जी,क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोरजी,ब्योर्न फोर्टुइन,मार्को येनसन,केशव महाराज,क्रेना मफाका, एडेन मारक्रम, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, रयान रिकेलटन और ट्रिस्टन स्टब्स।

साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज का शेड्यूल

24 सितंबर : पहला ओडीआई, हॉलीवुडबेट्स किंग्समीड स्टेडियम,डरबन

27 सितंबर : दूसरा ओडीआई डीपी वर्ल्ड वांडरर्स स्टेडियम,जोहान्सबर्ग

30 सितंबर:- तीसरा ओडीआई एनडब्ल्यूसी ओवल,पॉचेफस्ट्रम

माटेओ मेसी का कमाल : इंटर मियामी ने जीता नेपल्स कप

नई दिल्ली,07 सितम्बर 2026। महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के बेटे माटेओ ने अपने उभरते हुए फुटबॉल करियर में एक और कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इंटर मियामी एकेडमी को नेपल्स कप का खिताब जिताया। मेसी के दूसरे बेटे माटेओ ने मियामी एकेडमी की कप्तानी करते हुए नेपल्स कप जीता,जो उनके करियर की एक शानदार उपलब्धि है। जल्द ही 11 साल के होने वाले माटेओ अपने पिता के नक्शेकदम पर चल रहे हैं, जो 2022 वर्ल्ड कप विजेता हैं। सोशल मीडिया पर कई फैंस ने माटेओ की इस कामयाबी की तारीफ़ की। स्पेनिश जर्नल मार्का द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में माटेओ मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने ट्रॉफी के साथ पोज़ देते दिखे। उन्होंने कोपा नेपल्स ट्रॉफी पकड़ी हुई थी, जिस पर चैंपियन लिखा था। मेसी के तीन बेटे हैं, जिनमें माटेओ दूसरे नंबर पर हैं। वह 11 सितंबर को अपना 11वां जन्मदिन मनाएंगे। फुटबॉल के इस दिग्गज के दो और बेटे हैं - थियागो और सिरो। थियागो सबसे बड़े हैं और अभी 13 साल के हैं। सिरो तीनों में सबसे छोटे हैं और अभी आठ साल के हैं। मेसी ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल रिटायरमेंट की पुष्टि की, जिससे अर्जेंटीना के साथ उनके शानदार 21 साल के करियर का समापन हुआ। उन्होंने एक बयान में कहा कि उन्हें इस फैसले से दुःख हुआ है, लेकिन अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। मेसी ने अपने बयान में लिखा, समय कम होता जा रहा है, अध्याय खत्म होते हैं, और यह एक ऐसा अध्याय है जो मुझे बहुत दुखी करता है। मुझे नेशनल टीम का हिस्सा रहना पसंद है, हमेशा पसंद रहा है और हमेशा पसंद रहेगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपना सब कुछ दिया है, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, और इसके अलावा, मेरे बाद कुछ बहुत अच्छे युवा खिलाड़ी आ रहे हैं जो मौका पाने के हकदार हैं।

जीसीएल में गंगेज ग्रैंडमास्टर्स का बड़ा उलटफेर,टेबल टॉपर को 9-7 से हराया

बेंगलुरु ,07 सितम्बर 2026। ग्लोबल चेस लीग (GCL) के चौथे सीजन में गंगेज ग्रैंडमास्टर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टेबल टॉपर FYERS American Gambits को 9-7 से हरा दिया। इस जीत के साथ गंगेज ग्रैंडमास्टर्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। यह American Gambits की मौजूदा सीजन की पहली हार थी। गंगेज ग्रैंडमास्टर्स के लिए दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम को अपने पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन Alpine APL Pipers के खिलाफ 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि टीम ने इस हार को पीछे छोड़ते हुए अगले ही मुकाबले में शानदार वापसी की और लगातार

दो मैच जीतकर आ रही American Gambits की टीम को रोक दिया। पोलिना शुवालोवा ने एक बार फिर गंगेज ग्रैंडमास्टर्स के लिए अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बिबिसारा असाउबायेवा को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और प्लेयर ऑफ द मैच बनीं। इयान नेपोम्नियाच्ची ने भी महत्वपूर्ण मुकाबले में 2026 कैंडिडेट्स विजेता जावोखिर सिंदारोव को मात देकर अपनी टीम को अहम अंक दिलाए। सिंदारोव समय के दबाव में मुकाबला गंवा बैठे। FYERS American Gambits की ओर से निहाल सरीन ने जीत दर्ज की,लेकिन यह टीम को मुकाबला जिताने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई। वहीं डेनियल डुबोव अपनी बेहतर स्थिति को जीत में नहीं बदल सके और लेनियर डोमिंगेज के खिलाफ उनका मुकाबला 101 चालों के बाद ड्रॉ रहा।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं बबन पाल, आठ श्री भोला पाल, आयु 43 वर्ष, निवासी सुभाषनगर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र मे नाम आईसा पाल (Aisha pal) दर्ज है, जबकि मेरे पुत्री के आधार कार्ड में आईसा (Aisha) दर्ज हो गया है। जिसका आधार नम्बर 51094542 4143 है।

यह कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर सही नाम आईसा पाल (Aisha pal) दर्ज करवाने हेतु मैं स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

सपथकर्ता
बबन पाल
सुभाषनगर अम्बिकापुर,
जिला सरगुजा (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला - सूरजपुर,छ0ग0

रा0 प्र0क्र0 ब/121 वर्ष
ग्राम- सम्बलपुर प0ह0न0...19

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विमला भगत आ0 स्व0 मनीराम जाति उरांव निवासी ग्राम सम्बलपुर पह0नं019 रा0नि0म0 पिलखा तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र/पुत्री पिता स्व. मनी राम का मृत्यु दिनांक 18/05/2005 को ग्राम सम्बलपुर में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत सम्बलपुर को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 16/09/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायायल में पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/09/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील **कार्यपालिक दण्डाधिकारी लटोरी,जिला-सूरजपुर**

न्यायालय नायब तहसीलदार भैयाथान जिला - सूरजपुर,छ0ग0

रा0 प्र0क्र0 ब/121 वर्ष
ग्राम- सम्बलपुर प0ह0न0...11

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संतराम पिता शुगल जाति कंवर निवासी ग्राम कुसमुसी .प.ह.न. 11 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र अवि कुमार पैकरा का जन्म दिनांक 06/09/2008 को ग्राम कुसमूसी में हुई है, अज्ञानतावश जन्म/मृत्यु पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र अवि कुमार पैकरा का जन्म/मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुसमुसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 17/9/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 03/9/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील **कार्यपालिक दण्डाधिकारी भैयाथान,जिला-सूरजपुर**

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला- सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0/ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नर्मदा प्रसाद आ. रामजतन यादव, निवासी ग्राम खैरबार, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम केशवपुर में खसरा नंबर 17, 298, 299, 300, 343, 350, 351, 352, 353 रकबा क्रमशः 0.364, 0.089, 0.024, 0.166, 0.291, 0.125, 0.247, 0.862, 0.045 हे. भूमि के राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम त्रुटिवश ननकी अंकित हो गया है जबकि आवेदक का वास्तविक नाम नर्मदा प्रसाद है। आवेदक के द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जाँच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 18/09/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 25/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील **तहसीलदार**
अम्बिकापुर, सरगुजा

हाईकोर्ट ने 2015 और 2016 भर्ती को एक साथ जोड़ने पर उठाए सवाल,वरिष्ठता सूची निरस्त

सर्वेश यादव, सिद्धार्थ पांडे सहित निजी प्रतिवादियों से जुड़ा मामला, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को 60 दिन में पुनर्विचार के निर्देश

28 अप्रैल 2026 के आदेश ने खाद्य विभाग की नियुक्ति और पदोन्नति प्रक्रिया पर खड़े किए नए सवाल, खोजी खबरों का आधार बना न्यायालय का रिकॉर्ड

-न्यूज डेस्क-

रायपुर/बिलासपुर,07 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में नियुक्तियों,वरिष्ठता और पदोन्नति को लेकर उठे विवाद को उस समय नया मोड़ मिला,जब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने WPS क्रमांक 3163/2022 (Aparna Arya एवं अन्य बनाम राज्य शासन एवं अन्य) में 28 अप्रैल 2026 को महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची पर गंभीर आपत्ति दर्ज की,माननीय न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने पाया कि वर्ष 2015 और 2016 की अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं से नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को एक ही वरिष्ठता सूची में सम्मिलित कर दिया गया था,जो प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सामान्य सेवा शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12 के अनुरूप नहीं था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

न्यायालय ने अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद पाया कि वर्ष 2015 और 2016 की नियुक्तियां अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओं से हुई थीं,इसलिए दोनों को एक ही वरिष्ठता सूची में क्लब करना नियमों के विपरीत है,इसी आधार पर न्यायालय ने 18 नवंबर 2021 को नियंत्रक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया तथा याचिकाकर्ताओं को नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए नियंत्रक को 60 दिनों के भीतर पूरे मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

यहीं से शुरू हुआ बड़ा विवाद

दैनिक घटती-घटना द्वारा प्रकाशित खोजी समाचारों में इसी न्यायालयीन आदेश और उपलब्ध विभागीय दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियों,वरिष्ठता सूची,पदोन्नति तथा भर्ती नियमों के पालन को लेकर प्रश्न उठाए गए थे,समाचारों में यह नहीं कहा गया था कि कोई अधिकारी दोषी है,बल्कि यह प्रश्न उठाया गया था कि यदि स्वयं उच्च न्यायालय ने वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज की है, तो उसके आधार पर आगे हुई पदोन्नतियों और प्रशासनिक निर्णयों की भी निष्पक्ष समीक्षा होना आवश्यक है।

क्या था पूरा मामला?- याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपरना आर्या,राखी ठाकुर और सरिता पटेल द्वारा दायर की गई थी, याचिका में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2015 में हुई थी,जबकि निजी प्रतिवादी सर्वेश यादव, सिद्धार्थ पांडे एवं अजय सिंह की नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई,इसके बावजूद विभाग ने वरिष्ठता सूची में वर्ष 2016 में नियुक्त अधिकारियों को वर्ष 2015 के अधिकारियों से ऊपर स्थान दे दिया, जिससे उनकी वरिष्ठता और भविष्य की पदोन्नति प्रभावित हुई।

राज्य सरकार ने क्या कहा?- राज्य शासन की ओर से न्यायालय में यह तर्क दिया गया कि वरिष्ठता सूची छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सामान्य सेवा शर्तें) नियम,1961 के नियम 12 के अनुसार तैयार की गई है तथा निजी प्रतिवादी चयन सूची में ऊपर होने के कारण उन्हें वरिष्ठता सूची में भी ऊपर रखा गया।

लीगल नोटिस के बाद फिर चर्चा में आया मामला- इसी विषय पर प्रकाशित समाचारों के बाद दो अधिकारियों की ओर से दैनिक घटती-घटना को 50 लाख की क्षतिपूर्ति मांगते हुए कानूनी नोटिस भेजा गया है,नोटिस में समाचारों को मानहानिकारक बताया गया है, जबकि समाचार पत्र का कहना है कि उसके समाचार न्यायालयीन रिकॉर्ड,उपलब्ध दस्तावेजों और सार्वजनिक महत्व के विषयों पर आधारित खोजी रिपोर्टिंग का हिस्सा हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल-

क्या उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विभाग ने वरिष्ठता सूची और उससे जुड़े पदोन्नति संबंधी निर्णयों की पूरी तरह समीक्षा की? यदि समीक्षा हुई तो उसका परिणाम क्या रहा? यदि नहीं हुई,तो क्या न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया? और यदि पालन किया गया,तो उससे जुड़े अभिलेख सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए?

जांच से ही सामने आएगी सच्चाई

यह पूरा मामला अब केवल वरिष्ठता सूची का विवाद नहीं रह गया है,बल्कि विभागीय पारदर्शिता,भर्ती प्रक्रिया और पदोन्नति व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है,विशेषज्ञों का मानना है कि यदि विभाग के सभी निर्णय नियमों के अनुरूप हैं तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा,वहीं यदि कहीं प्रक्रिया में त्रुटि हुई है,तो उसका निराकरण भी आवश्यक है,दैनिक घटती-घटना का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं,बल्कि न्यायालयीन अभिलेखों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक महत्व के विषयों को सामने लाना है,लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे प्रश्नों का उत्तर जांच और पारदर्शिता से दिया जाना चाहिए,ताकि तथ्य जनता के सामने स्पष्ट रूप से आ सकें।

90 दिन में चार्जशीट मिलने पर निलंबन खत्म नहीं होगा

हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटा कोरबा के कर्मचारी ने लगाई थी याचिका

बिलासपुर,07 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन अवधि से जुड़े नियमों को स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है, जिसमें 90 दिन बाद जारी एक्सटेंशन आदेश को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि,छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत अगर किसी निलंबित कर्मचारी को 90 दिन के भीतर विभागीय चार्जशीट दे दी गई है, तो निलंबन को आगे बढ़ाने का आदेश जारी न होने मात्र से सस्पेंशन अपने आप खत्म नहीं माना जाएगा। कोरबा कलेक्टोरेट में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 शिवम सहाय चौहान को आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद 25 मार्च 2022 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था। कर्मचारी को तय समय सीमा के भीतर 20 अप्रैल 2022 को विभागीय चार्जशीट दे दी गई थी,लेकिन उनके निलंबन को आगे बढ़ाने का आदेश करीब डेढ़ साल बाद 28 अगस्त 2023 को जारी किया गया था।

विभागीय चार्जशीट देने के बाद भी निलंबन आदेश को आगे बढ़ाने के खिलाफ कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी,जिसमें डेढ़ साल बाद निलंबन आदेश को नियम विरूद्ध बताया। वहीं,हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इस देरी को आधार बनाते हुए पूर्व में सिंगल बेंच ने कर्मचारी के निलंबन आदेश और एक्सटेंशन आदेश को रद्द कर बहाली का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य शासन ने डिवीजन बेंच में अपील की थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश बने कृष्ण राम महापात्र

राज्यपाल रमेन डेका ने लोकभवन में दिलाई शपथ...पहले ओडिशा हाईकोर्ट में थे सीनियर जज

रायपुर 07 सितम्बर 2026। जस्टिस कृष्ण राम महापात्र ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम् में आयोजित समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ के बाद राज्यपाल ने महापात्र को बधाई और शुभकामनाएं दीं। शपथ ग्रहण से पहले प्रदेश के मुख्य सचिव विकास शील ने राष्ट्रपति की ओर से जारी वारंट का वाचन किया। इसके बाद राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र को राष्ट्रपति द्वारा जारी मूल वारंट की प्रति सौंपी।

ओडिशा हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश रहे : कृष्ण राम महापात्र इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी मिली है। वे प्रदेश के 16वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।

सीएम साय समेत कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद : शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय,उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा,स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तोखन साहू मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,पूर्व राज्यपाल रमेश बैस,राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक सुनील सोनी और अनुज शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी समारोह में शामिल हुए। मुख्य न्यायाधीश महापात्र की धर्मपत्नी अनिता महापात्र और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीशगण भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

वरिष्ठ अधिकारी और अधिवक्ता भी शामिल हुए : समारोह में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम,राज्यपाल के सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना,महाधिवक्ता विवेक शर्मा और हाईकोर्ट बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी समारोह में हिस्सा लिया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)